₹ 10

www.kewalsachtimes.com

अगस्त 2024

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO.-1317729, POSTAL REG. NO.:-PS-78

हैवानियत की

हदें पार

जन-जन की आवाज है केवल सच

केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

Kewalachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

BHIM UPI
G Pay Paytm

www.kewalsach.com www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

काजोल
05 अगस्त 1974

वेंकटेस प्रसाद
05 अगस्त 1969

कपिल सिब्बल
08 अगस्त 1948

महेश बाबू
09 अगस्त 1975

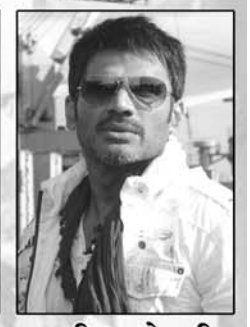

सुनील शेट्टी
11 अगस्त 1961

सीताराम येचुरी
12 अगस्त 1952

स्व०श्रीदेवी कपूर
13 अगस्त 1963

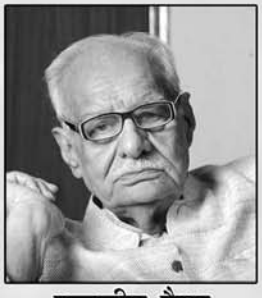

कुलदीप नैयर
14 अगस्त 1923

सुनीधी चौहान
14 अगस्त 1983

अदनान सामी
15 अगस्त 1973

अरविन्द केजरीवाल
16 अगस्त 1968

सैफ अली खान
16 अगस्त 1970

दलेर मेंहदी
18 अगस्त 1967

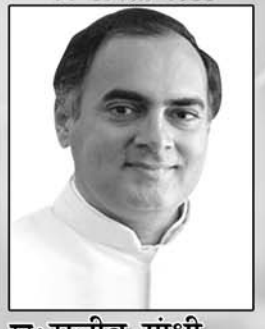

स्व०राजीव गांधी
20 अगस्त 1944

रणदीप हुड्डा
20 अगस्त 1976

चिरंजिवी
22 अगस्त 1955

मधुर भंडारकर
26 अगस्त 1966

मेनका गांधी
26 अगस्त 1956

दिलीप सिंह खली
27 अगस्त 1972

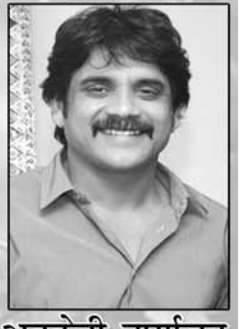

अक्केनी नार्गाजुन
29 अगस्त 1959

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
COLOUR	Cover Page	3,00,000/-	N/A
	Back Page	1,00,000/-	65,000/-
	Back Inside	90,000/-	50,000/-
	Back Inner	80,000/-	50,000/-
	Middle	1,40,000/-	N/A
	Front Inside	90,000/-	50,000/-
	Front Inner	80,000/-	50,000/-
B & W	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
	Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

हिन्दू और मुसलमान में फंसा हिन्दुस्तान

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

''

2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भले हीं केन्द्र में NDA की सरकार बन गयी हो लेकिन भगवान श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या से BJP की पराजय ने हिन्दूओं को सकते में डाल दिया है। 500 वर्षों के परिश्रम एवं बलिदान के बाद जब रामलला ने अयोध्या के भव्य मंदिर में स्थान ग्रहण किया और आवाम को लगा कि भारत अब हिन्दूराष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ेगा क्योंकि ''**अबकी बार - 400 पार**'' की संख्या भारतीय राजनीति को बदल देगी लेकिन चुनाव के परिणाम ने देश को धर्म संकट में डाल दिया क्योंकि 400 पार तो दूर अपने दम पर सरकार बनाने के लायक भी BJP नहीं बची और अयोध्या से भी पराजित हो गयी। देश की राजनीति में एक दल सनातन धर्म को प्राथमिकता दे रहा है वहीं विपक्ष के साथ सत्तापक्ष के भी दल सनातन धर्म में विशेष कोई आस्था नहीं रखता बल्कि कुर्सी के खेल में वह साथ है। भारत का गौरवशाली इतिहास को जिस प्रकार धूमिल करने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है और सत्तालोभी उसका समर्थन कर रहे हैं उससे तो साफ हो चुका है कि हिन्दुस्तान हिन्दू और मुसलमान की राजनीति में बंट चुका है। भगवान के प्रति भी घृणित भाव रखकर राजनीति करना देश को गर्त में धकेलने जैसा है।

''

बाबर की दोगली सोच पर विचार करने के बजाय बाबर को ही भारत का सच्चा हितैषी बताना फिर से गुलामी की ओर ले जाने के लिए काफी है। अल्पसंख्यक राजनीति को प्राथमिकता देने वाले दल लोकतंत्र एवं संविधान में आस्था तो दिखाते हैं लेकिन जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हैं, वहां उनपर हो चुके एवं हो रहे जुल्म पर मौनी बाबा बनकर सनातन धर्म का मजाक बनाते हैं और तो और कश्मीर और बांग्लादेश वाला स्थिति भारत के कई राज्यों में धड़ल्ले से चल रहा है। कश्मीर, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, केरल, तामिलनाडू तो खुलकर हिन्दुओं को टारगेट कर रहा है कि सनातन धर्म पर एक पर एक तल्ख टिप्पणी करके उनका अपमान करते हैं और सत्ता पर काबिज रहने के लिए हिन्दू होकर भी मोदी-योगी को उखाड़ फेंकने के लिए सदन के भीतर भी दंगा-फसाद वाला बयान देने से बाज नहीं आते। पूरे विश्व में सनातन धर्म के लिए भारत ही एक ऐसा देश है जहां हिन्दुओं का जनसंख्या अधिक है लेकिन जिस प्रकार मुगल और ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के गौरवशाली इतिहास को ध्वस्त कर दिया और आजादी के बाद देश के विभाजन हुआ और पाकिस्तान बनने के बाद 1947 से लगातार भारत पर अटैक हो रहा है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है का साख रखता है लेकिन इस देश का संविधान के भीतर की कूटनीति अब देश की जनता के सामने आने लगा है। जिस भीम राव अम्बेडकर की दुहाई देकर विपक्ष मोदी-योगी की सरकार को घेरने के लिए किसी भी हद तक गिर रहे हैं और सदन के भीतर मणिपुर के मामला हो या फिर सीएए के मुद्दा पर विपक्ष कुर्सी के लिए यह भी दावा करता है कि भारत में भी बांगलादेश जैसा माहौल बन जायेगा। धर्म के नाम पर पाकिस्तान के अलग हो जाने के भी भारत में धर्म की कूटनीति कायम रही और वोट के लिए राजनेता किस प्रकार राष्ट्र के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं यह सार्वजनिक हो चुका है। 2024 का लोकसभा चुनाव के दो ही नतीजों को अगर गौर से समझेंगे तो यह स्पष्ट हो जायेगा की देश के भीतर किस प्रकार हिन्दु, हिन्दुस्तान और मुसलमान की राजनीति हावि है। अयोध्या और बनारस संसदीय क्षेत्र में हिन्दुवादी विचार का किस प्रकार कत्ल हुआ है यह इसी से समझा जा सकता है कि राम मंदिर का निर्माण करने वाली भाजपा वहां चुनाव हार जाती है और हिन्दुओं पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी जीत जाती है और तो और बनारस से स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। अयोध्या एवं काशी कोरिडोर में जहां सनातन का सम्मान विश्व स्तर पर बढ़ा है वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन की राजनीति ने भाजपा के 400 के पार के आंकड़े को ध्वस्त करते हुए 272 का आंकड़ा भी अपने दम पर भाजपा पार करने में असफल रही और देश में हिन्दु, हिन्दुस्तान और मुसलमान की राजनीति में मशगूल होता जा रहा है। मुस्लिम वोट के लिए भाजपा ने तीन तलाक और केन्द्र की योजनाओं में बगैर भेदभाव के देश के जरूरतमंद लोगों के बीच पहुंचाये गये परन्तु मुस्लिम वोटर ने मोदी के क्षेत्र में ही उनको ठेंगा दिखाया गया। देश के भीतर हिन्दु और मुसलमान की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है और दोनों गठबंधन में आपसी मतभेद भी है लेकिन देश के भीतर जिस प्रकार भगवान के उपर गंदी बयानबाजी हो रही है तथा देश के भीतर रेप की घटना पर भी घृणित राजनीति को बल दिया जा रहा है। विपक्ष को अब मोदी से अधिक योगी से खतरा मंडरा रहा है क्योंकि बिना लाग-लपेट के स्पष्ट शब्दों में सनातन पर चर्चा करने के साथ-साथ समाज को जागृत कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे वहीं विपक्ष दूसरे देश के घुसपैठियों को जायज ठहरा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार बांगलादेश से अवैध घुसपैठ को जायज बनाने की कोशिश चल रही है उससे साफ हो जाता है कि हिन्दुस्तान में कैसे हिन्दु और मुसलमान हो रहा है। भारत आगे बढ़े उससे कहीं ज्यादा चिंता इस बात की है कि किसी प्रकार सत्ता पर काबिज हों। भारत में गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई है और समय रहते सावधान नहीं हुए तो कोई भी हादसा से गुजरना होगा।

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

वर्षः- 14, अंकः- 158 माहः- अगस्त 2024 रू. 10/-

Editor

Brajesh Mishra 9431073769
6206889040
8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

Principal Editor

Arun Kumar Banka 7782053204
Surjit Tiwary 9431222619
Nilendu Kumar Jha 9431810505

General Manager (H.R)

Triloki Nath Prasad 9308815605

General Manager (Advertisement)

Manish Kamaliya 6202340243
Poonam Jaiswal 9430000482

Joint Editor/Lay-out Editor

Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor

Amitabh Ranjan Mishra 8873004350
S. N. Giri 9308454485

Asst. Editor

Mithilesh Kumar 9934021022
Sashi Ranjan Singh 9431253179
Rajeev Kumar Shukla 7488290565
Kamod Kumar Kanchan 8971844318

Sub. Editor

Arbind Mishra 6204617413
Prasun Pusakar 9430826922
Brajesh Sahay 7488696914

Bureau Chief

Sanket kumar Jha 7762089203
Sagar Kumar 9155378519

Bureau

Sridhar Pandey 9852168763
Sonu Kumar 8002647553

Photographer

Mukesh Kumar 9304377779

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड

संजय कुमार सिन्हा 9868700991

झारखण्ड हेड

ब्रजेश मिश्र (2) 7979769647
7654122344

पश्चिम बंगाल हेड

अजीत दुबे 9433567880
9339740757

मध्यप्रदेश हेड

अभिषेक पाठक 8109932505
8269322711

छत्तीसगढ़ हेड

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश हेड

निर्भय कुमार मिश्रा 9452127278

उत्तराखण्ड हेड

आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड

आवश्यकता है

गुजरात हेड

आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

पंजाब हेड

आवश्यकता है

हरियाणा हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

उड़ीसा हेड

आवश्यकता है

आसाम हेड

आवश्यकता है

हिमाचल हेड

आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
मो०- 9868700991, 9431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 9433567880, 9339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव, द्वितीय त्तल,
फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 9308815605

मध्यप्रदेश कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अभिषेक कुमार पाठक
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
मो०- 8109932505,

विशेष प्रतिनिधी

भारती मिश्र 8521308428
बेंकटेश कुमार 8210023343

प्रकाशित आलेख पर आप अपना सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दें।

केवल सच टाइम्स

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

हमारा पता है

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14,
मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
सम्पर्क करें:- 9431073769, 8340360961

हमारा ई-मेल

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

जुलाई 2024

बीजेपी में रार

मिश्रा जी,

मैं आपकी द्विभाषीय पत्रिका केवल सच टाइम्स का नियमित पाठक हूं और इसको वेबसाइट पर पढ़ता हूं और पीडीएफ फाइल को फेसबुक पर भी लोड करता हूं. जुलाई 2024 अंक में भाजपा का यूपी में क्या हो रहा है की जानकारी समीरात्मज मिश्र की खबर **''यूपी बीजेपी में रार!''** में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच की राजनीति और केंद्र के खास का हस्तक्षेप ने विपक्ष को शक्ति दी है. दोनो नेताओ के बीच गंदी राजनीति करके योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने एवं उनकी लोकप्रियता को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

● **कृतिका शर्मा, बाबू बाजार, कोलकाता**

एंकाउंटर

संपादक महोदय,

जुलाई 2024 अंक में नवीन रंगियाल की खबर जिस **गैंगस्टर का इनकाउंटर हो गया उसकी मौत पर आज भी क्यों मचा है बवाल?** में पूरी घटना को पूरी सच्चाई को सामने रखकर विषय को उठाया है. केवल सच टाइम्स पत्रिका अपनी बेबाकी के लिए खास स्थान रखती है. आनंद पाल की आपराधिक गतिविधियों को भी रखा गया है लेकिन इस देश में कानून से ऊपर राजनीति को महत्व दिया जाता है. अपराधी से अगर राजनीतिक दल को लाभ होगा तो उसको कैसे मासुम बनाया जाए और सरकार को घेरा जाए उसके लिए आंदोलन शुरू किया जाता है. यह खबर काफी चिंताजनक है।

● **कमलेश यादव, सेक्टर-10, नोयडा, यूपी**

अन्दर के पन्नों में

खेल महाकुंभ

संपादक महोदय,

जुलाई 2024 अंक में अमित कुमार की खबर ''**फैशन की राजधानी में खेलों का महाकुंभ**'' में पेरिस ओलंपिक- 2024 में 117 भारतीय खिलाड़ियों के लेकर भारत में इसमें भाग लेने पहुंचा है की खबर वास्तव में बधाई योग्य है। केवल सच टाइम्स पत्रिका की खबर वर्त्तमान सहित पूर्व के कार्यक्रमों पर भी सही विश्लेषण के साथ लिखा जाता है। पेरिस में यह ओलंपिक खेल का महाकुंभ की चर्चा के साथ भारत में जमकर राजनीति भी होती रही है। भारत में खेल को भावना के साथ खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ राजनीति की जाती है और पक्ष एवं विपक्ष उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। यह खबर काफी संतोषजनक है।

● **मुकेश सिंह, टावर चौक, बक्सर, बिहार**

महालूट

संपादक महोदय,

आपका संपादकीय पूर्ण बेबाकी के साथ लिखा जाता है जिसकी वजह से इस पत्रिका का वजूद सरकार एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच बरकरार है। जुलाई 2024 अंक का संपादकीय ''**बिहार एवं झारखंड में महालूट**'' में आपने भ्रष्टाचार पर सटीक आलेख पाठकों के समक्ष रखा है की किस प्रकार राज्यों में जनता का राजस्व को सुनियोजित ढंग से लूटा जा रहा है। किसी भी विभाग में टेंडर का मामला से लेकर अन्य विकास कार्यों में हुए महालूट को भी सरकार पर्दा डालने का काम कर रही है। दोनों राज्यों में शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग में भयंकर लूट को अंजाम दिया गया और मामला उजागर होने के बाद भी कार्रवाई के बजाय पर्दा डाला जा रहा है। सटीक आलेख।

● **अभिषेक कुमार, अलका कॉलोनी, रातु, राँची**

नेमप्लेट विवाद

मिश्रा जी,

केवल सच टाइम्स पत्रिका के जुलाई माह 2024 में राजनीति की एक से बढ़कर एक खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमित कुमार की खबर **''कांवड़ यात्रा में नेमप्लेट विवाद''** में योगी आदित्यनाथ के सनातनी प्रयास ने कानून को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। अगर नाम का कोई मतलब नहीं होता तो फिर पक्ष एवं विपक्ष क्यों हमारी सरकार में ऐसा होता था और तुम्हारी सरकार में ऐसा। सावन माह में कांवड़ यात्रा को कोई दूषित नहीं करे इसके लिए योगी जी ने फल और अन्य दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को आदेश दिया है पर ओवैसी और अखिलेश ग्रुप ने कोहराम मचाया और सुप्रीम कोर्ट भी साथ दिया। ज्वलंत एवं सटीक खबर है।

●**वाचस्पति दुबे, गोधवलिया चौक, बनारस, यूपी**

केजरीवाल की जिंदगी

ब्रजेश जी,

संजय सिन्हा की जुलाई अंक 2024 की खबर केजरीवाल की जिंदगी से खेल रही है भाजपा में दिल्ली एवं आप और भाजपा की राजनीति पर बहुत सटीक और कारगर विश्लेषण किया है शराब घोटाले में जिस प्रकार जांच एजेंसी और न्यायालय की कारवाई ने केजरीवाल की राजनीति पर ग्रहण लगाया है उससे आवाम में यह संदेश जा रहा है कि भाजपा केजरीवाल के जिंदगी साथ खिलवाड़ कर रही है. ईडी ने जिस प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत कर रही है उसकी वजह से चर्चा हो रहा है तो केजरीवाल का सुगर भी कम ज्यादा की कूटनीति भी लोगों भी समझ से परे है. खबर में इसके लिए जिम्मेदार कौन है उसपर बेबाक खबर भी आना चाहिए.

● **महेन्द्र वर्णवाल, गणेश नगर, नई दिल्ली**

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)
पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका
एवं 'केवल सच टाइम्स'
एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020
फोन- 0612/3504251

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क
भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी
'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''
9060148110
sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
व्यवसायी
पटना, बिहार
7360955555

एक नजर

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
  e-mail:- kewalsach@gmail.com,
  editor.kstimes@rediffmail.com
  kewalsach_times@rediffmail.com
- स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**
- पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
- सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
- आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
- किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- सभी पद अवैतनिक हैं।
- विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।
- फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)
- कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
- **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
- भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।

A/C No.	:-	20001817444
BANK	:-	State Bank Of India
IFSC Code	:-	SBIN0003564
PAN No.	:-	AKKPM4905A

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of "APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

Registered Under the Indian Society Act 21, 1880

East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020

Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077

E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com

Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

APNA GHAR

Now in the State of Bihar & Jharkhand

Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence in the lives of many Sr. Citizens.

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

A/C No.	-	**0600010202404**
Bank Name	-	**United Bank of India**
IFSC Code	-	**UTBIOKKB463**
Pan No.	-	**AAAAK9339D**

हैवानियत की हदें पार
प्रशिक्षु चिकित्सक की हत्या फिर बलात्कार

● अमित कुमार

अप्रैल माह में जारी की गयी नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 में पश्चिम बंगाल में 1111 बलात्कार के मामले दर्ज किये गए हैं। उसी वर्ष प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 34738 मामले दर्ज किये गए थे। ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का दर 71.8 प्रतिशत था जबकि ये राष्ट्रीय औसत 65.4 प्रतिशत से काफी ज्यादा है। वैसे में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना ने न सिर्फ सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है बल्कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं।

बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या से पूरा देश आहत है। शराब का आदी, पोर्न वीडियो देखने का शौक, चार-चार शादियां और सेक्स व हैवानियत से भरा दिमाग। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर को बहुत बर्बरता से कत्ल करने और फिर उसकी लाश के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी संजय रॉय के बीमार दिमाग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। ट्रेनी महिला डॉक्टर के बर्बरतापूर्वक किए गए मर्डर से कोलकाता के साथ ही पूरे देश में बवाल मचा है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक के डॉक्टर विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं। आरोपी संजय रॉय पुलिस की हिरासत में है, उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस जांच में उसने जो खुलासे किए हैं, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके शरीर पर गंभीर चोटें थीं, जो मौत से पहले उसे दी गई थीं। शव परीक्षण में पीड़िता के सिर, दोनों गाल, होंठ, नाक, दाहिने जबड़े, ठोड़ी, गर्दन, बाएं हाथ, कंधे, घुटने और टखने के साथ-साथ उसके निजी अंगों के अंदर 14 से अधिक चोटें पाई गईं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पीड़िता के जननांग में एक सफेद, गाढ़ा, चिपचिपा तरल पदार्थ पाया गया है जो सिमेन हो सकता है। पीड़िता के रक्त और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के नमूने आगे की जांच के लिए भेजे गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़ों में रक्तस्राव और शरीर में अन्य जगहों पर खून के थक्के जमने का भी खुलासा किया गया है।

मीडिया में आई रिपोर्ट्स

के मुताबिक मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी ने महिला डॉक्टर की हत्या सोते समय ही कर दी थी। उसने पहले डॉक्टर का गला घोंटकर मारा, उसके बाद उसकी लाश के साथ दुष्कर्म किया। उसने हैवानियत दिखाते हुए मर चुकी डॉक्टर के शरीर पर कई वार किए। क्योंकि मौत हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए जख्मों से खून निकल रहा था। दरअसल, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने पीड़िता की मौत का कारण हाथ से गला घोंटना बताया है और मौत के तरीके को क्रूर हत्या बताया है। ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके गुप्तांग में जबरदस्ती प्रवेश/ प्रविष्ट करने के चिकित्सीय साक्ष्य मिले हैं, जिससे उसके साथ किए गए यौन उत्पीड़न की संभावना जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी बर्बरता को मिटाने के लिए सबूत मिटाने की कोशिश की। आरोपी संजय ने पूछताछ में बताया कि वारदात के बाद वह घर जाकर सो गया और सुबह उठकर अपने कपड़े-जूते धोए, क्योंकि उन पर खून लगा था। आरोपी के जूतों पर खून के धब्बे मिले हैं। पुलिस ने उसके कपड़े और जूते बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी संजय को शराब पीने और पोर्न वीडियो देखने की आदत है।

उसका फोन पोर्न और सेक्स वीडियोज से भरा पड़ा है। उसने डॉक्टर को मारने से पहले शराब पी थी और शराब पीते हुए उसने सेक्स वीडियो देखे थे।

गौरतलब है कि प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले के मुख्य आरोपी और 6 अन्य का 'पॉलीग्राफ टेस्ट' शुरू हो गया। मुख्य आरोपी संजय रॉय का 'पॉलीग्राफ टेस्ट' उस जेल में ही किया जा रहा है जहां वह बंद है। जिन लोगों का 'पॉलीग्राफ टेस्ट' हो रहा है, उनमें प्रथम वर्ष के 2 स्नातकोत्तर प्रशिक्षु भी शामिल हैं। 'पॉलीग्राफ टेस्ट' के दौरान व्यक्ति द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए जाते समय एक मशीन की मदद से उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है और यह पता लगाया जाता है कि वह सच बोल रहा है या झूठ। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपी संजय रॉय का 'पॉलीग्राफ टेस्ट' उस जेल में ही किया जा रहा है जहां वह बंद है, जबकि पूर्व प्राचार्य संदीप घोष, घटना की रात ड्यूटी पर मौजूद चार चिकित्सकों और एक नागरिक स्वयंसेवक समेत छः अन्य का 'पॉलीग्राफ टेस्ट' सीबीआई के कोलकाता स्थित कार्यालय में किया जा रहा है। जिन लोगों का 'पॉलीग्राफ टेस्ट' हो रहा है, उनमें प्रथम वर्ष के दो स्नातकोत्तर प्रशिक्षु भी शामिल हैं, क्योंकि जांचकर्ताओं को अस्पताल के उस सम्मेलन कक्ष के अंदर कथित तौर पर उनकी उंगलियों के निशान मिले हैं, जहां पीड़िता का शव मिला था। उन्होंने बताया कि दिल्ली के केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) से 'पॉलीग्राफ' विशेषज्ञों का एक दल कोलकाता पहुंच गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उच्चतम न्यायालय से कहा था कि स्थानीय पुलिस ने प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले को दबाने का प्रयास किया था और जब तक संघीय एजेंसी ने जांच अपने हाथ में ली, तब तक अपराध स्थल से छेड़छाड़ की जा चुकी थी। हत्या की घटना के खिलाफ देशभर में व्यापक विरोध

प्रदर्शन हो रहे हैं।

बताते चले कि कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 9 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के सेमीनार हॉल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु चिकित्सक का शव मिला था, जिस पर गंभीर चोटों के निशान थे। शव मिलने के एक दिन बाद 10 अगस्त को रॉय को गिरफ्तार किया था। सीसीटीवी फुटेज और चिकित्सक के शव के पास एक ब्लूटुथ उपकरण मिलने के बाद रॉय की गिरफ्तारी की गई थी जिसे कॉलेज के सेमीनार हॉल में प्रवेश करते हुए कथित तौर पर देखा गया जहां सुबह करीब चार बजे शव मिला था। रॉय 2019 से नागरिक स्वयंसेवक के रूप में कोलकाता पुलिस के साथ काम कर रहा था। प्रशिक्षित मुक्केबाज रॉय ने पिछले कुछ वर्षों में कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कथित तौर पर करीबी बना ली थी जिसके बाद उसे कोलकाता पुलिस कल्याण बोर्ड में शामिल किया गया और आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की पुलिस चौकी में तैनात कर दिया गया। उसने अपने खिलाफ आरोपों से इनकार किया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि स्थानीय पुलिस ने प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और

उसकी हत्या के मामले को दबाने का प्रयास किया था और जब तक संघीय एजेंसी ने जांच अपने हाथ में ली, तब तक अपराध स्थल से छेड़छाड़ की जा चुकी थी। वही प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के माता-पिता ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को बताया कि इस अपराध में उसी कॉलेज के कुछ इंटर्न और चिकित्सक शामिल हैं। सीबीआई को भी माता-पिता ने बताया कि उन्हें अपनी बेटी के यौन उत्पीड़न और हत्या के पीछे कई लोगों के शामिल होने का संदेह है। उन्होंने हमें आरजी कर अस्पताल में अपनी बेटी के साथ काम करने वाले कुछ इंटर्न एवं डॉक्टरों के नाम बताए हैं। केंद्रीय एजेंसी ने कम से कम 30 नामों पर ध्यान केंद्रित किया है। सीबीआई ने अस्पताल के उस कर्मी और दो स्नातकोत्तर प्रशिक्षु (पीजीटी) को तलब किया जो घटना की रात डॉक्टर के साथ ड्यूटी पर थे।

दूसरी तरफ 17 अगस्त को देशभर के डॉक्टरों ने हड़ताल की घोषणा की है। प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर देशभर में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों के प्रमुखों को ड्यूटी पर तैनात किसी स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ हिंसा की घटना के मामले में छह घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज करनी होगी। हालांकि इस घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी रही। आईएमए द्वारा 24 घंटे के लिए देश भर में गैर-आपातकालीन और ओपीडी सेवाएं बंद रखने के आह्वान के बाद, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के अधिकाधिक चिकित्सक कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और पीड़ित के लिए न्याय और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय कानून की मांग की। बता दे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब

और गुजरात सहित कई शहरों में रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध मार्च निकाला। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय कानून पर विचार-विमर्श के लिए एक समिति गठित करने के निर्णय को 'बहुत कम और बहुत देर से लिया गया' करार देते हुए आईएमए प्रमुख डॉ. आरवी. अशोकन ने बताया कि हितधारकों के परामर्श के बाद 2019 में एक मसौदा विधेयक तैयार किया गया था, लेकिन यह कभी संसद में नहीं गया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कानून लाने के लिए सिर्फ राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के निदेशकों और चिकित्सा अधीक्षकों तथा सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को भेजे गए कार्यालय ज्ञापन में मंत्रालय ने कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी भी स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की स्थिति में, संस्थान के प्रमुख घटना के अधिकतम 6 घंटे के भीतर संस्थागत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जिम्मेदार होंगे। सनद! रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म-हत्या मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए बंगाल सरकार और पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने मामले में सीबीआई से स्टेट्स रिपोर्ट मांगी। अदालत ने आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपने के आदेश दिए। शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार और पुलिस से कड़े सवाल करते हुए मामले पर कड़ी चिंता जताई। उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि हजारों लोगों की भीड़ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कैसे घुसी? अदालत ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा बेहद कमजोर है। यह डॉक्टरों की सुरक्षा का सवाल है। ज्यादातर युवा चिकित्सक 36 घंटे काम करते हैं, हमें काम करने की सुरक्षित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है। पीठ ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया और डॉक्टरों से भी हड़ताल खत्म करने की अपील की। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा लगता है कि अपराध का पता सुबह-सुबह ही चल गया था लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। अदालत ने सवाल किया कि एफआईआर में देर क्यों हुई, क्या मर्डर कहा गया? अस्पताल में तोड़फोड़ हुई तो पुलिस क्या कर रही थी? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और काम करने की स्थितियां सुरक्षित नहीं हैं तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं। अदालत ने मीडिया में मृतका का नाम प्रकाशित होने पर भी चिंता जताई। वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार की नीति बलात्कार संबंधी घटनाओं को कतई बर्दाश्त न करने की है। इन मामलों से संबंधित मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित किया जाएगा, ताकि दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मृत्युदंड सुनिश्चित किया जा सके। बनर्जी ने कहा कि यदि राज्यपाल संशोधित विधेयक को मंजूरी देने में देरी करते हैं या इसे अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो वह राजभवन के बाहर धरने पर

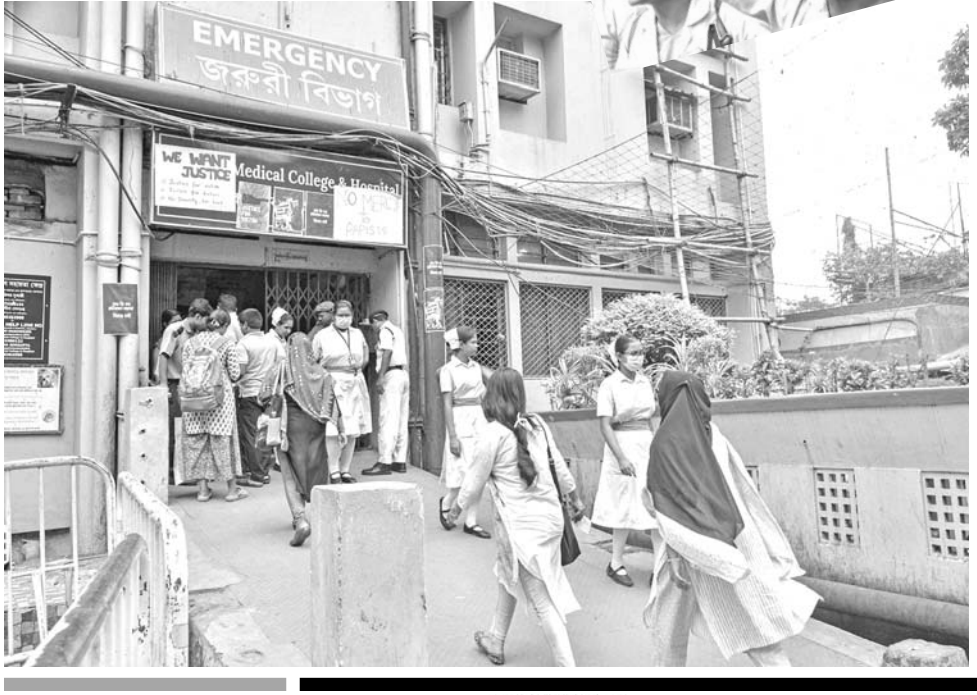

बैठेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में जमीनी स्तर पर आंदोलन शुरू करेगी, ताकि बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड देने का कानून पारित करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया जा सके। बनर्जी ने बंगाल के प्रदर्शनकारी कनिष्ठ चिकित्सकों से भी काम पर लौटने का आग्रह किया। ये चिकित्सक 20 दिन से हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के इस मुद्दे के प्रति शुरू से ही मेरी सहानुभूति रही है, क्योंकि वे अपनी सहकर्मी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना के इतने दिन बीत जाने के बावजूद हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हम आपका दर्द समझते हैं, लेकिन कृपया अब काम पर लौट आएं क्योंकि मरीज परेशान हैं।

बहरहाल, वैसे तो पिछले एक महीने में बच्चियों के साथ हुए बर्बर दुष्कर्मों ने पूरे देश को हिलाया है किंतु कोलकाता के आईजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की घटना ने समाज के हर वर्ग को उद्वेलित किया है। यह बिलकुल स्वाभाविक है। मेडिकल कॉलेज के अंदर एक डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध, फिर स्वयं अस्पताल प्रशासन की भूमिका, पुलिस प्रशासन से लेकर पूरी सरकार के व्यवहार ने डर पैदा किया है। शायद पहली बार सुनने में किसी को अतिश्योक्ति लगे इस घटना के आलोक में पश्चिम बंगाल की पूरी सरकार, अपराधियों और माफियाओं के वर्चस्व वाली दिखी है। सत्ता से जुड़ा कोई भी पक्ष मृतका के न्याय के लिए खड़ा होता नहीं दिखा। इसके विपरीत अस्पताल से लेकर सत्ता की संपूर्ण कोशिश मामले में न्याय की गुंजाइश खत्म करने तथा न्याय की मांग करने वालों को धमकी-धमकी व हिंसा से रोकने की रही है। राजधानी दिल्ली के 2012 के निर्भया कांड से तुलना करने वाले कई पहलू की अनदेखी करते हैं। उसमें पीड़िता बस में अकेलेपन की शिकार हुई, निर्जन स्थान पर उसका अर्ध मृत शरीर फेंका गया तथा प्रशासन का व्यवहार ऐसा नहीं रहा जिस तरह हमने पश्चिम बंगाल को देखा है। उस समय भी सरकार और पुलिस प्रशासन की भूमिका किसी तरह मामले को आगे न बढने देने या बड़ा बवंडर से बचने की थी। बावजूद यह नहीं कह सकते कि घटना को दूसरा रूप देने या सप्ताह की निर्लज ताकत से न्याय की मांग को समाप्त करने की रही। ऐसे जघन्य और वीभत्स कांड पर कोई सरकार इस तरह का व्यवहार करें यह कल्पना से परे है। अस्पताल में करीब 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद महिला डॉक्टर वहां सो रही हो और दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी जाए तो अस्पताल प्रशासन की पहली भूमिका क्या होनी चाहिए? पुलिस को तुरंत सूचित करना, मामला दर्ज करवाना तथा परिवार को सच्ची जानकारी देकर उन्हें अस्पताल बुलवाना और साथ खड़ा रहना। कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इसके उलट कुछ लोगों के साथ मिलकर इसे आत्महत्या साबित करने, परिवार को काफी समय बाद झूठी जानकारी देने और डॉक्टरों की टीमों को अलग-अलग जिम्मेवारी देकर पूरे मामले को खत्म करने का षड्यंत्र किया। लड़की के माता-पिता को आज तक नहीं पता कि बेटी की आत्महत्या करने का फोन किसने किया। अस्पताल में आने के बाद शव देखने के लिए उन्हें 3 घंटे से ज्यादा प्रतीक्षा करनी पड़े और एक व्यक्ति पीठ पर हाथ रखने वाला नहीं हो तो उनकी क्या दशा हुई होगी इसकी कल्पना से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिना प्राथमिकी के और टीम बनाएं पोस्टमार्टम करना और फिर अपने नियंत्रण में ही शव दहन कर देना। इन सबको मिला दीजिए तो दुष्कर्म करने वाले से बड़ा अपराधी अस्पताल प्रशासन और पुलिस दिखेगा? पुलिस अस्पताल प्रशासन के निर्देशानुसार भूमिका निभाती रही। पुलिस का पहला प्रश्न यही होना चाहिए कि आरंभ में हमें सूचना क्यों नहीं दी? पोस्टमार्टम के

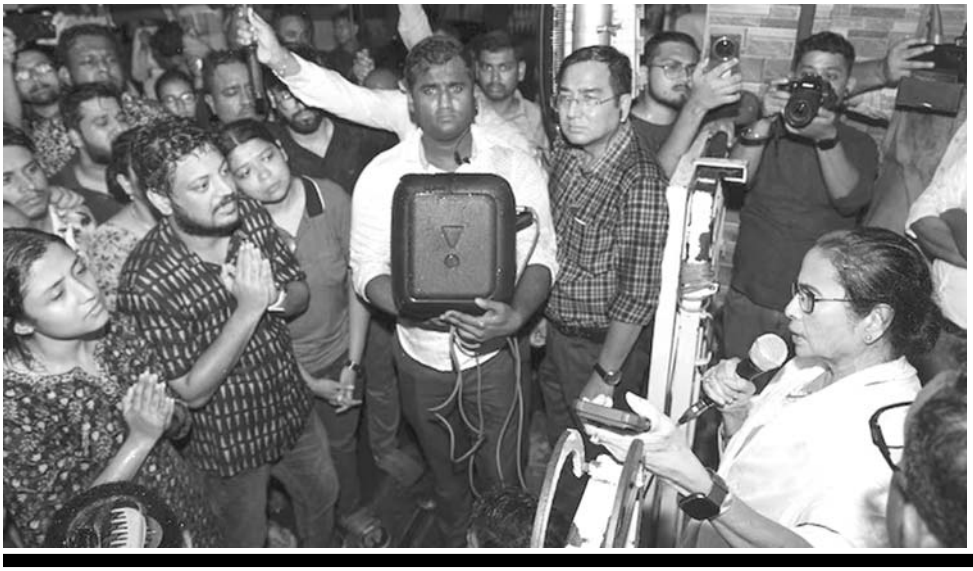

बाद प्राथमिकी क्यों लिखवा रहे हैं? इसके उलट कोलकाता पुलिस आयुक्त से लेकर पूरा पुलिस महकमा घटना को रफा-दफा करने में लगा रहा। पुलिस कमिश्नर का वक्तव्य था कि सारा कुछ मीडिया के कारण हो रहा है। सोशल मीडिया से लेकर मुख्य मीडिया तक आवाज उठाने वाले जो संज्ञान में आये पुलिस का त्वरित नोटिस मुकदमा भुगतने को तैयार रहें। इस तरह की धमकी थोड़ी बहुत उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान आता था, लेकिन इतना व्यापक नहीं। स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध करने वालों के विरुद्ध मोर्चाबंदी की और उन्होंने मार्च कर विरोध भी जताया। तृणमूल कांग्रेस या सरकार के किसी प्रवक्ता ने इसका उत्तर नहीं दिया कि आखिर मुख्यमंत्री किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहीं थीं? उन्होंने सारी समस्या की जड़ राम और वाम यानी भाजपा और वामपंथी दलों को घोषित कर दिया। उनके राज्यसभा सांसदों ने घटना की आलोचना करते हुए कुछ प्रश्न उठाएं तो उन्हें सजा भुगतनी पड़ी। इस तरह चारों तरफ डर और आतंक का वातावरण बनाया गया ताकि कोई विरोध करने का साहस न करे। ममता बनर्जी का सड़क पर उतरना उनके कार्यकर्ताओं, समर्थकों और प्रशासन के लिए सीधा संदेश था कि विरोध करने वाले बंगाल में उथल-पुथल मचाना चाहते हैं इसलिए उन्हें हर हाल में रोका जाए। राम करीब 30% मुसलमानों के लिए संदेश था कि खतरा तुम पर भी है। परिणाम-ऊपर से गांव तक उनके लोग सक्रिय होकर ऐसा वातावरण बनाते रहे कि कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो। अभी निचले स्तर से समाचार आना शेष है कि कितने लोगों को सरकारी तंत्र का कोपभजन बनना पड़ा है। अलग-अलग विभागों ने पत्र जारी किया कि विभागीय भूमिका से परे कुछ भी अनुशासनहीनता माना जाएगा। स्कूल इंस्पेक्टर के पत्र गए कि स्कूलों में छात्रों की शिक्षा के अलावा कोई भी गतिविधि स्वीकार नहीं होगी। इसी बीच हमने देखा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर न्याय के लिए धरना दे रहे डॉक्टरों पर हिंसक हमले हुए, उन्ह पीटा गया, उनकी सारी व्यवस्था तहस-नहस कर दी गई और अस्पताल में भी तोड़फोड़ हुई। किसी भी न्यायसंगत लोकतांत्रिक धरना या आंदोलन को सुरक्षा देने का दायित्व पुलिस प्रशासन का होता है। कानून के विरुद्ध हो तो उन्हें हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने का दायित्व भी पुलिस का है। पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो उसे पता होना चाहिए कि इन्हें सुरक्षा न देना आपराधिक कृत्य ही होगा। धरना देने वालों के साथ हिंसा और पिटाई हो रही थी मानो कानून और व्यवस्था का नाम निशान नहीं हो। जब मुख्यमंत्री ही घटना की संवेदनशीलता को स्वीकार कर मृतका के परिवार के साथ खड़ा होने और न्याय दिलाने के लिए कदम उठाने की जगह विरोधियों के विरुद्ध सड़कों पर उतर जाएं तो यही होता है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू किया तथा मामला सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया तब भी मुख्यमंत्री की तीखी प्रतिक्रिया देखने लायक थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 90% जांच पूरी कर ली है इसलिए सीबीआई को दो दिनों में मामला पूरा करना चाहिए। उन्होंने चार दिन के अंदर दोषी को फांसी देने तक की भी मांग कर दी। उच्चतम न्यायालय में संज्ञान लेने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के साथ 21 बड़े अधिवक्ता सरकार की ओर से खड़े हैं। उनकी एक दिन की फीस कितनी होगी इसकी कल्पना करिए? आखिर वकीलों की वह टीम क्यों खड़ी हो रही है? क्या मृतका और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने या फिर सरकार के हर व्यवहार की रक्षा करने? अगर ममता सरकार एक छोटा शपथ पत्र उच्चतम न्यायालय में डाल देती कि जो कुछ हुआ वह सरकार को स्वीकार्य नहीं है और न्यायालय जो निर्देश देगा उसका पालन करते हुए सरकार न्याय दिलाने तथा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी तो वकीलों की इतनी बड़ी फौज खड़ी नहीं करनी पड़ती। अभी तक की छानबीन से पता चल रहा है कि पूरा बंगाल ऐसे ही तंत्र के हाथों है। आईजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल को हटाने के बाद नेशनल मेडिकल कॉलेज को प्रिंसिपल बना देना बता रहा था कि उनकी पहुंच कितनी बड़ी है। पता चल रहा है कि ममता बनर्जी के निजी चिकित्सक उनके साथ हैं। अस्पताल में भारी पैमाने पर हर स्तर पर भ्रष्टाचार और अपराध के काले कारनामे सामने आ रहे हैं और लगता है जैसे ऊपर से नीचे तक पूरा गैंग इसमें सक्रिय हो जिन्हें कानून का कोई भय नहीं। जिस संजय राय पर कांड का आरोप है वह सिविल वालंटियर है जिसे ममता बनर्जी ने 2011 में शासन में आने के बाद स्थापित किया। यह वैसे ही है जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने सिविल डिफेंस बनाया। ये वहां पार्टी के लोग माने जाते हैं और इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता तभी तो अस्पताल के अंदर उसकी इतनी बड़ी हैसियत थी। कुल मिलाकर गहराई से देखें तो ऐसा लगेगा कि एक समय अपने ईमानदारी और संघर्ष के लिए जानी जाने ममता मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता के हर स्तर स्वास्थ्य, पुलिस, प्रशासन में जकड़े माफियाओं, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के तंत्र की प्रमुख बन गई है और पूरा पश्चिम बंगाल इनके शिकंजे में है।

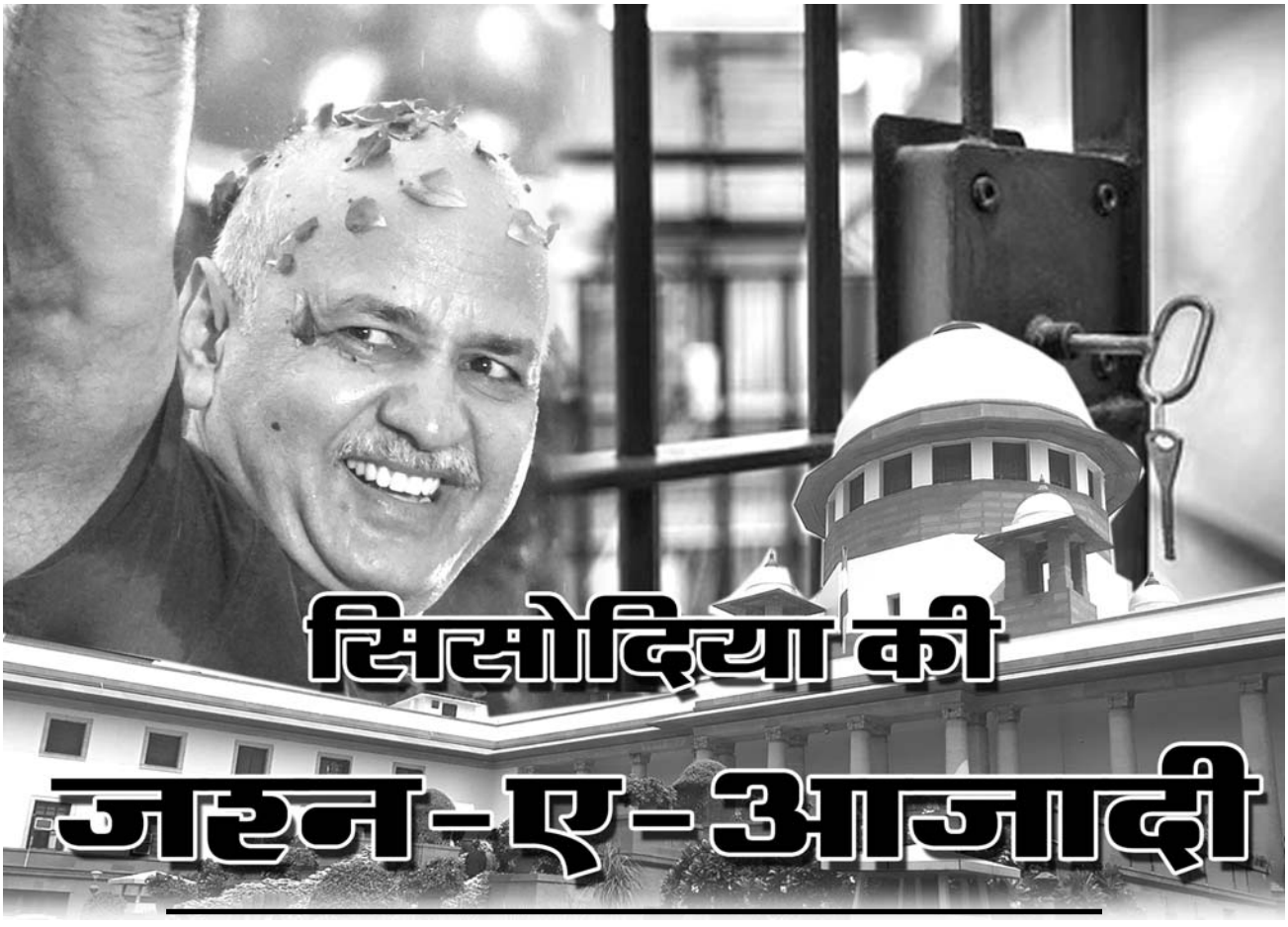

सिसोदिया की जश्न-ए-आजादी

● संजय सिन्हा

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। 17 महीने बाद जेल से बाहर आये। सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने के एक दिन बाद अपनी पत्नी के साथ सुबह की चाय पीते हुए एक तस्वीर साझा की। इसे 17 महीने बाद एक आजाद सुबह की पहली चाय शीर्षक दिया। सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले के सिलसिले में लगभग 17 महीने से जेल में थे। उच्चतम न्यायालय ने सिसोदिया को जमानत दे दी, जिसके बाद यह उनका पहला पोस्ट है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपने पोस्ट में लिखा, 'आजाद सुबह की पहली चाय... 17 महीने बाद।' वह आजादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी है। वह आजादी जो ईश्वर ने हमें सबके साथ खुली हवा में सांस लेने के लिए दी है। सिसोदिया ने आजादी वाली चाय के बाद कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद वे राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वही सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज के साथ मंदिर पहुंचे। पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए मंदिर परिसर में एकत्र हुए थे और उनके पहुंचते ही उन्होंने 'जय श्री राम' और 'जय हनुमान' के नारे लगाए। इस अवसर पर सिसोदिया ने कहा कि भगवान हनुमान दिल्ली के लोगों का भला करें। वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से देश में तानाशाही के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग संविधान से ज्यादा ताकतवर नहीं हैं। सिसोदिया ने यहां पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को इस तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा, जो न केवल नेताओं को जेल में डाल रही है बल्कि नागरिकों को भी परेशान कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता ने दावा किया कि जब वे जेल में थे तो उन्हें जमानत मिलने की चिंता नहीं थी लेकिन उन्हें यह देखकर पीड़ा हुई कि व्यापारियों को फर्जी मामलों

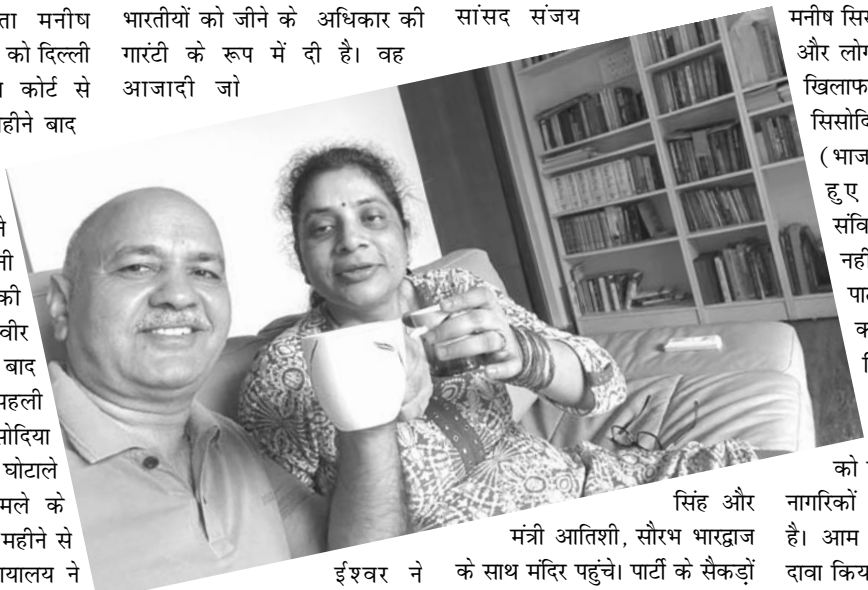

में सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भाजपा को चंदा नहीं दिया। अपने संबोधन में सिसोदिया ने पार्टी प्रमुख एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया और उन्हें देश में ईमानदारी का प्रतीक करार दिया। केजरीवाल भी इसी मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल के काम को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है और अगर विपक्ष के नेता इस तानाशाही के खिलाफ एकजुट हो जाएं तो केजरीवाल 24 घंटे में जेल से बाहर आ जाएंगे। सिसोदिया ने जमानत मिलने के फैसले पर कहा कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की शक्ति का इस्तेमाल कर तानाशाही को कुचल दिया। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि 7-8 महीने में न्याय मिल जाएगा लेकिन इसमें 17 महीने लग गए, अंतत: सत्य की जीत हुई। वही दूसरी ओर सिसोदिया ने राज्यपाल के पद को लेकर बड़ी बाते कही। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह संस्था लोकतंत्र पर बोझ बन गई है और इसकी भूमिका केवल गैर-राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) दलों की सरकारों के कामकाज में बाधा डालना रह गई है। हमें राज्यपाल की क्या आवश्यकता है। निर्वाचित सरकार को शपथ दिलाने के लिए? यह काम अन्य संस्थाएं भी कर सकती हैं। सरकारों को गिराने के अलावा उनका क्या काम है? इसके अलावा वे क्या कर रहे हैं? सिसोदिया ने कहा, राज्यपाल एक संस्था के रूप में इस देश में बोझ बन गए हैं। वे निर्वाचित सरकार के कामकाज में बाधा डालने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा न केवल दिल्ली में है, बल्कि पश्चिम बंगाल, केरल जैसे अन्य राज्यों में भी समस्याएं पैदा कर रहा है। वही उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच टकराव के कारण दिल्ली में नौकरशाह परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इससे वह दुखी हैं। उन्होंने अफसोस जताया कि विभिन्न स्तरों पर शासन में विभाजन के कारण सार्वजनिक सेवाएं और कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं तथा लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञात हो कि दिल्ली में उपराज्यपाल कार्यालय और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के बीच शासन संबंधी कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। 'आप' के वरिष्ठ नेता ने कहा, लोकतंत्र की हत्या के कारण उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच टकराव है। केंद्र सरकार ने चुनी हुई सरकार के अधिकार छीन लिए हैं। जब लोकतंत्र की हत्या होती है तो सभी पक्ष प्रभावित होते हैं। यहां तक कि सरकार के अधिकारी भी त्रस्त हैं और मुझे उनके लिए दुख है। सिसोदिया ने दावा किया कि नौकरशाह लोगों के कल्याण के लिए काम करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें ऊपरी स्तर से कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने याद दिलाया कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि निर्वाचित सरकार के पास निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन केंद्र इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, वे निर्वाचित सरकार के अधिकारों को छीनने के लिए संसद के माध्यम से कानून लेकर आए। इसे मैं लोकतंत्र की हत्या कहता हूं।

बहरहाल, जमानत पर रिहा होने के अगले दिन सिसोदिया राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को नमन किया। वही आम आदमी पार्टी ने

सिसोदिया पर आरोप

- कोविड में दुकान बंद रहने पर शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रु की छूट दी गई।
- शराब का लाइसेंस लेने वालों को फायदा पहुंचाया। जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
- एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रु की रकम लौटाई, वो जरूरी NOC लेने में नाकाम रही।
- बिजनेसमैन अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाने के लिए सिसोदिया को करीब 2.2 करोड़ की घूस मिली।
- 2021-22 में जिनको शराब के लाइसेंस मिले उनको टेंडर होने के बाद बेजा फायदा पहुंचाया गया।
- सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 फोन, 43 सिम कार्ड बदले। 5 सिम सिसोदिया के नाम पर थे।
- मनीष सिसोदिया जो एक्साइज विभाग के मंत्री थे उन्होंने एक्साइज नीति के खिलाफ फैसले लिए।

एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा था कि 'सत्यमेव जयते। दिल्ली वालों की दुआएं हुई कामयाब, तमाम झूठ और षड्यंत्रों का जाल तोड़कर 1. 5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी।' आप नेता राघव चड्ढा ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया जी को बेल मिलने से पूरे देश में आज खुशी है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। मनीष जी को 530 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। उनका जुर्म इतना था कि उन्होंने गरीबों के बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया। प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापिस आ रहे हैं। आप नेता संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई। उन्होंने सवाल किया कि सिसोदिया के 17 महीने कौन लौटाएगा? वही मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर शीर्ष अदालत ने कहा कि सिसोदिया को 10-10 लाख के 2 मुचलकों पर जमानत दे दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर शर्त लगाते हुए निर्देश दिया कि वे अपना पासपोर्ट जमा कर दें तथा गवाहों को प्रभावित न करें। साथ ही उन्हें हर सोमवार जेल में हाजिरी देनी होगी। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 माह से हिरासत में हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है जिससे वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं। पीठ ने कहा कि इन मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना ठीक नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय इस बात को समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। वही सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 17 महीने की जेल मनीष सिसोदिया काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा ईडी ने कहा था कि ये ट्रायल 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा, वो होता नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि ईडी का आरोप खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने ट्रायल में देरी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी है, ये ऐतिहासिक फैसला है। दूसरी तरफ सिसोदिया की जमानत की खबर से आप नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी इस खबर को सुनकर भावुक हो गई। आतिशी को जब यह खबर मिली वे द्वारका के नसीरपुर में एक वर्ल्ड क्लास स्कूल उद्घाटन कर रही थीं। उन्होंने कहा कि इस स्कूल का शिलान्यास मनीष सिसोदिया ने ही किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शिक्षा जगत की क्रांति की जीत बताया। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को सत्य की जीत करार देते हुए उम्मीद जताई कि जेल में बंद पार्टी के अन्य नेताओं को भी न्याय मिलेगा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि 17 महीने के इंतजार के बाद एक बड़ी सफलता मिली। लेकिन मैं आज भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि यह आपकी दुर्भावना की राजनीति कब तक चलेगी? उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की तानाशाही पर जोरदार तमाचा है। आपने उस व्यक्ति को 17 माह जेल में रखा जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर रहा था। आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने से आज पूरे देश में खुशी है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा, मनीष जी को 530 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने गरीबों के बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया। प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापस आ रहे हैं।

गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने से पार्टी को ऐसे समय में बड़ी राहत मिली है जब वह अगले कुछ महीनों में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव और दिल्ली चुनाव की तैयारी कर रही है। उच्चतम न्यायालय से सिसोदिया को जमानत मिलने का 'आप' के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था क्योंकि पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में अपने शीर्ष नेताओं के जेल में बंद होने के कारण अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जूझ रही है। सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले सिसोदिया दिल्ली सरकार का न केवल प्रमुख चेहरा थे, बल्कि महत्वपूर्ण समय में संकट से निपटने और राजनीतिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर

'आप' का रुख सामने रखने के लिए पार्टी के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति भी थे। उनके न केवल पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल बल्कि कई अन्य नेताओं के साथ भी अच्छे संबंध थे। इसलिए उनकी गिरफ्तारी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका थी, जो किसी तरह इस स्थिति से निपटने में सफल रही, लेकिन उनकी अनुपस्थिति से कभी पूरी तरह से उबर नहीं सकी। हरियाणा विधानसभा चुनाव और दिल्ली चुनाव से पहले सिसोदिया को जमानत मिलना संकटग्रस्त पार्टी के लिए बड़ी राहत की बात है। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि सिसोदिया की रिहाई 'आप' को बदनाम करने के अभियान के लिए झटका है। वरिष्ठ पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने कहा, सिसोदिया बहुत अच्छा काम कर रहे थे और उन्हें एक फर्जी मामले में 17 महीने तक जेल में रखा गया। पाठक ने कहा, उनकी गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के लोगों में गुस्सा था और उनकी रिहाई से हमारी पार्टी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम पिछली बार से दो या चार सीट ज्यादा जीतेंगे। वास्तव में मुझे लगता है कि हम विपक्ष का सूपड़ा साफ करेंगे। पार्टी नेताओं का मानना है कि सिसोदिया की मौजूदगी से उनके चुनाव प्रचार अभियान को खासकर दिल्ली में मजबूती मिलेगी, जहां पार्टी लगातार तीसरी बार जीत की उम्मीद कर रही है और 2015 एवं 2020 जैसा प्रदर्शन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जब उसने कुल 70 सीट में से क्रमशः 67 और 62 सीट जीती थीं। 'आप' के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा, सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आप कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। इसका असर आने वाले चुनावों में दिखेगा। हमें उम्मीद है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। 'आप' के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के कारण पार्टी के लिए 2022 से 2024 तक का समय उथल-पुथल भरा रहा है। इस अवधि के दौरान पार्टी ने चुनावी लाभ और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने तक का सफर देखा है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सफर अत्यधिक उतार-चढ़ाव भरा रहा है। यह सब मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धनशोधन के मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुआ। उसी वर्ष जुलाई में उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों को लेकर आबकारी नीति की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश की थी। इस घटनाक्रम ने सिसोदिया की गिरफ्तारी की अटकलें को हवा दी थी जिन्होंने उस नीति को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस नीति के तहत 32 क्षेत्रों में विभाजित राष्ट्रीय राजधानी में 849 दुकानों के लिए निजी बोलीदाताओं को खुदरा लाइसेंस दिए गए थे।

सनद् रहे कि सिसोदिया ने खुद अपनी गिरफ्तारी के बारे में भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे 'आप' को तोड़ने और भाजपा से हाथ मिलाने के लिए संपर्क किया था। उन्हें आखिरकार सीबीआई ने 26 फरवरी को और फिर अगले महीने आबकारी नीति से जुड़े ध नशोधन मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। जैन के साथ उन्होंने पिछले साल दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया गया। कुछ महीने बाद अक्टूबर में सिंह को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनकी किस्मत अपनी पार्टी के अन्य सहयोगियों की तुलना में अच्छी रही और उन्हें इस वर्ष अप्रैल में जमानत मिल गई। वही ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें मई में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। उन्होंने दो जून को आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्हें 26 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। हालांकि मुख्यमंत्री को ईडी मामले में उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई मामले के कारण वे अब भी जेल में हैं। सिसोदिया की जमानत से पार्टी में उम्मीद जागी है कि केजरीवाल और जैन भी जल्द ही बाहर आ सकते हैं। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की तथा कहा कि वह तानाशाही की बेड़ियां तोड़कर जेल से बाहर आए हैं। उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए सिसोदिया के साथ मान की यह पहली मुलाकात थी। मान ने मुलाकात के बाद कहा, आज मेरी मुलाकात उस नेता और उस व्यक्ति से हुई है जो शिक्षा की क्रांति लेकर आया है। डेढ़ साल बाद तानाशाही की बेड़ियां तोड़कर वह जेल से बाहर आए हैं। जब उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो अदालत से हमें न्याय मिला। उन्होंने कहा कि आज अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन के मौके पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। मान ने कहा, आज उनका जन्मदिन है, इसलिए मैंने उनकी पत्नी से मुलाकात की। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने तानाशाही की दीवारें तोड़कर जमानत हासिल की और सच्चाई की लड़ाई जीती, उसी तरह हमारे नेता (केजरीवाल) भी जल्द ही बाहर आएंगे।

सिसोदिया को जमानत सुप्रीम कोर्ट की 3 शर्तें

मनीष सिसोदिया ED और CBI मामले में 10-10 लाख का बेल बॉन्ड भरें।

अपना पासपोर्ट जमा करें, सबूतों-गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।

हर सोमवार और गुरुवार को नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा।

EC announces schedule for assembly elections 3 Phase polls in J&K and Haryana

The Election Commission of India announced the schedule for Assembly elections in Jammu Kashmir and Haryana here on Friday. The voting will take place in Jammu and Kashmir in three phases on September 18 in the first phase, September 25 in the second phase and 1st October in the third and final phase. Counting will be held on 4th October. There are 90 seats in the J&K Assembly post delimitation, with 43 seats in the Jammu region and 47 seats in Kashmir. J&K has been without an elected House for five years since the abrogation of Article 370. Election will be held in Jammu and Kashmir after a gap of ten years as the last assembly election was held in 2014. The PDP-BJP coalition government fell in June 2018 when the latter withdrew support to the then-Chief Minister Mehbooba Mufti. In Haryana the voting will take place in a single phase on October 1, and the counting of votes will be held on October 4. The term of the Haryana Assembly is ending in November. The announcement was made by the Chief Election Commissioner Rajiv Kumar, after visiting both J&K and Haryana to review poll preparations recently. Addressing a press conference,

Rajiv Kumar said the total number of electors in Jammu and Kashmir is 87.09 lakh. Out of which, 44.46 Lakh are men and 42.62 lakh are female voters. 3.71 lakh are first-time voters and 20.7 lakh are young voters". "Of the 90 assembly constituencies in Jammu and Kashmir, 74 are general, SC-7 and ST-9" he said.

The CEC said the Amarnath Yatra will end on August 19 and the final voter list will also be published on August 20." When asked about the recent terror attack in Jammu Kashmir, the CEC said that we will provide all necessary security arrangements as sought by the administration. He added that the people of Jammu and Kashmir are really to accept the challenge posed by the terrorists. On the Lok Sabha election held in Jammu and Kashmir, Rajiv Kumar said, "The long queues at the polling booth in the UT during the Lok Sabha election are proof that people not only want change but also want to raise their voice by becoming a part of that change". "This glimpse of hope and democracy shows that the people want to change the picture. They want to write their own destiny. The people of Jammu and Kashmir chose a ballot over a bullet in the the Lok Sabha election" he further added. On August 14, the Election Commission held a meeting with Union Home Secretary Ajay Bhalla to review the security situation in Jammu and Kashmir. In December last year, the Supreme Court had directed the Centre to conclude the election process in the Union territory by September 30, 2024.

Jammu and Kashmir : What to expect as elections return?

Jammu and Kashmir is set for a local election, the first to vote in their local administration since 2014, with the polling set to be held in three phases between September 18 and October 1.

The union territory took part in the national polls this summer, with chief election commissioner Rajiv Kumar saying people chose "ballots over bullets" and praising the 58% turnout in June. While announcing the local poll schedule in Jammu and Kashmir, Kumar said he hopes for a similar response in the upcoming vote.

The Himalayan region, which is claimed by both India and Pakistan, has been embroiled in violence since the start of armed insurgency there in 1989. Tens of thousands of people have been killed in the ensuing violence.

☞ **New Delhi still in control :-** During the last such election, Jammu and Kashmir were still considered a state. State governments were elected every six years, but the last one, the coalition of regional Peoples Democratic Party (PDP) and Bharatiya Janata Party (BJP), did not last a full term — it was elected in 2014 and lost its majority in 2018. Then, in 2019, the government of Prime Minister Narendra Modi revoked Jammu and Kashmir's semi-autonomous status and split the state into two federally administered territories.

This granted New Delhi much more direct control over the restive region that has struggled with an Islamist insurgency for decades. And even after the local polls are done and the new administration is in place, its officials will still have to leave many key decisions about the region's economy and security to the national government in New Delhi and to its local representative, Lieutenant Governor Manoj Sinha.

☞ **'We are determined to have statehood restored' :-** A spokesman for the PDP told DW that his party wants to see the region regain its status as one of India's states. "This is not what we hoped for and want statehood restored. But at least we will have people's representation in the assembly and a voice for the people that has not been heard," PDP spokesperson Mohit Bhan said. Another regional political party, the Jammu and Kashmir National Conference, has already vowed to push for an India-Pakistan dialogue on Kashmir, introduce laws to protect jobs and land, and seek the release of political prisoners.

☞ **It also wants local officials to regain their former power :-** "We are determined to have statehood restored. The government has already made this promise to the Supreme Court. If it does not restore statehood willingly, we will pursue justice through the court. With statehood, the government of Jammu and Kashmir will have the powers required to fulfill promises," the National Conference vice president, Omar Abdullah, told local media.

More deadly attacks in Jammu :- The election revival is taking place amid an uptick in violence. On July 8, five Indian army soldiers were killed and five others were injured in an ambush by militants on an army convoy in Kathua district. In June, at least nine people were killed and 33 injured when a bus carrying Hindu pilgrims plunged into a deep gorge after a militant attack in Reasi district. Experts have noted that more and more violent incidents are reported in the Jammu region of Jammu and Kashmir, which had mostly been spared of violence in the past. In the first six months of 2024, 17 people were killed in Jammu, compared to 12 for the entirety of last year.

झामुमो में दिखने लगी बगावत

मेरे जीवन का नया अध्याय होगा शुरू : चंपई

● अमित कुमार

राजनीति में उतराधिकारी अपनो को बनाने की परंपरा राजा-महराजाओं के जमाने से चला आ रहा है और एक उदाहरण बिहार प्रदेश भी है जहां सत्ता की कुर्सी का उतराधिकारी बनाने का प्रयोग एक बार नहीं बल्कि दो-दो बार हुआ। एक बार तो तब जब कथित मामलों में तत्कालिन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा था और बेउर जेल में बंद थे तब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर उतराधिकारी बनाया था। लालू जी तक तो यह प्रयोग कामयाब रहा किन्तु कहते हैं कि शराब और सत्ता का नशा एक जैसा ही होता है वैसे में इसकी जब आदत हो जाये तो कोई भी इसका मोह नहीं छोड़ना चाहता। बिहार में ही याद कर लिजिए उस वक्त को जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहली बार दलित कार्ड खेलने के लिए जीतन राम मांझी को बिठाया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद मांझी अपनी ही मनमानी करने लगे, फिर उनपर पद और कुर्सी छोड़ने के दबाब बनने लगे और आखिर में उन्हें पद और कुर्सी को त्यागना पड़ा और इसका प्रभाव यह हुआ कि उन्होंने दल और वरीय नेता नीतीश कुमार से बगावत करके अपना ही दल बना लिया। आज मांझी केन्द्र में मंत्री हैं और अपनी पहचान एक मजबूत नेता के तौरपर बना ली है। खैर! बात झारखण्ड की हो रही है तो यहां भी बिहार जैसा ही प्रयोग हुआ और अब यह बगावत को दिशा दे दी है। बता दें कि कथित आरोप में झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सीएम की कुर्सी खाली होने पर पार्टी सुप्रिमो शिबू सोरेन के करीबी रहे चंपई सोरेन को झारखण्ड का बिहार के तत्कालिन सीएम मांझी समझ मुख्यमंत्री बनाया गया। किन्तु जेल से बाहर आने के बाद उन पर भी कुर्सी छोड़ने का राजनीतिक दबाब मिलने लगा और अंतोगत्वा चंपई ने मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग दिया किन्तु कुर्सी का मोह अभी भी उनके साथ है, ऐसा झामुमो नेताओं के बीच कहना है।

गौरतलब है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रांची में कहा कि वे राजनीति नहीं छोड़ेंगे और नया सियासी दल बनाने का विकल्प उनके लिए हमेशा खुला है। सोरेन ने कहा कि वे झामुमो नेताओं के हाथों अपमान का सामना करने के बाद अपनी योजनाओं पर अडिग हैं। इस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) को समर्पित कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के वरिष्ठ नेता ने सरायकेला-खरसावां जिले में अपने पैतृक गांव झिलिंगोरा पहुंचने के तुरंत बाद कहा कि यह मेरे जीवन का नया अध्याय है। मैं राजनीति नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे अपने समर्थकों से बहुत प्यार और समर्थन मिला है। अध्याय समाप्त हो गया है, मैं एक नया संगठन बना सकता हूं। बता दे कि सोरेन को 1990 के दशक में पृथक राज्य बनाने की लड़ाई में उनके योगदान के लिए 'झारखंड का टाइगर' उपनाम दिया गया था। झारखंड को 2000 में बिहार के दक्षिणी भाग से अलग करके बनाया गया था। चंपई सोरेन ने कहा कि झामुमो से किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया है। यह झारखंड की धरती है। मैंने छात्र जीवन से ही संघर्ष किया है। मैंने

पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के नेतृत्व में अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन में हिस्सा लिया था। झामुमो नेता ने कहा कि अगर उन्हें समान विचारधारा वाला संगठन मिलता है तो वे किसी भी संगठन से हाथ मिला सकते हैं। उन्होंने 18 अगस्त को 'एक्स' पर की गई अपनी पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि मैंने वही पोस्ट किया, जो मुझे उचित लगा। पूरा देश जानता है कि मैंने क्या सोचा? भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच वरिष्ठ नेता ने कहा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें घोर अपमान का सामना करना पड़ा जिसके कारण उन्हें वैकल्पिक रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। चंपई सोरेन ने कहा था कि इतने अपमान के बाद मुझे वैकल्पिक रास्ता तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि जुलाई के पहले सप्ताह में उनके सभी सरकारी कार्यक्रम पार्टी नेतृत्व द्वारा उनकी जानकारी के बिना अचानक रद्द कर दिए गए थे। चंपई सोरेन ने कहा, "पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा तीन जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है और मुझसे कहा गया कि तब तक आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते।" उन्होंने सवाल किया, "क्या लोकतंत्र में इससे अधिक अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे?" चंपई सोरेन ने दावा किया, "कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था।'' पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, लेकिन आत्म-सम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था।" उन्होंने लिखा कि भावुक होकर वह आंसुओं को संभालने में लगे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''लेकिन उन्हें (मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना उनका हवाला देते हुए) सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा, मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसके लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।'' उन्होंने कहा कि इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुईं, जिसका जिक्र वह फिलहाल नहीं करना चाहते हैं। चंपई सोरेन ने कहा, ''मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है।'' उन्होंने कहा, ''उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक, इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं।'' चंपई सोरेन ने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है और वह नहीं चाहते हैं कि कोई अन्य पार्टी सदस्य इसमें शामिल हो या संगठन को कोई नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा, ''मैं उस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी नहीं सोच सकता जिसे हमने अपने खून-पसीने से सींचा है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बना दी गई हैं कि..'' पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन स्वास्थ्य कारणों से राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। अगर वह सक्रिय होते तो चीजें अलग होतीं। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन (3 जुलाई) तक, मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह, हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े-बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए, उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। झामुमो नेता चंपई सोरेन के पाला बदलने की अटकलों के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त करने और समाज को बांटने का आरोप लगाया। सोरेन का यह बयान झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के दिल्ली पहुंचने के कुछ घंटों बाद आया। गोड्डा जिले में एक सरकारी समारोह को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा गुजरात, असम और महाराष्ट्र से लोगों को लाकर ''आदिवासियों, दलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के बीच जहर फैलाने और उन्हें एक-दूसरे से लड़वाने'' का काम कर रही है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ''समाज की बात तो भूल ही जाइए, ये लोग परिवारों और दलों को तोड़ने का काम करते हैं।

वे विधायकों की खरीद-फरोख्त करते हैं। पैसा ऐसी चीज है कि नेताओं को इधर-उधर जाने में ज्यादा समय नहीं लगता।'' हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि झारखंड में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव कार्यक्रम ''निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं, बल्कि राज्य में विपक्षी पार्टी (भाजपा) द्वारा तय किया जाएगा।'' उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग अब संवैधानिक संस्था नहीं रह गया है, क्योंकि इस पर भाजपा के लोगों का कब्जा हो गया है।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उन्हें (भाजपा को) चुनौती देता हूं कि अगर आज विध ानसभा चुनाव हुए तो झारखंड से उनका सफाया हो जाएगा।

सनद् रहे कि भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की संभावनाओं को लेकर उनके साथ अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। मरांडी ने कहा कि चंपई एक मंझे हुए नेता हैं और वह अपनी आगे की राह के बारे में निर्णय खुद लेंगे। भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच चंपई दिल्ली पहुंचे थे। बाद में उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अत्यधिक अपमान झेला, जिसके बाद वह वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गए। मरांडी ने कहा, चंपई सोरेन से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। वह एक मंझे हुए नेता हैं और झारखंड राज्य के गठन के लिए चलाए गए आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं। वह अपनी आगे की राह के बारे में निर्णय खुद लेंगे। चंपई के सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा, इससे संकेत मिलता है कि वह बहुत आहत हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उससे उन्होंने काफी अपमानित महसूस किया। चंपई ने पोस्ट में बताया कि तीन जुलाई को पार्टी विधायकों की बैठक में उनसे इस्तीफा देने को कहा गया। उन्होंने कहा कि वह इस निर्देश से आहत थे, क्योंकि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार, उन्होंने बैठक में घोषणा की कि आज से मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। उन्होंने कहा कि उनके पास तीन विकल्प हैं, पहला-राजनीति से सन्यास ले लें, दूसरा-एक नई पार्टी बनाएं और तीसरा-कोई सहयोगी मिले तो उसका दामन थाम लें। चंपई ने कहा, उस दिन से लेकर अब तक और आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक, इस यात्रा में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हैं। भाजपा द्वारा विधायकों की खरीद-फरोख्त करने संबंधी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आरोपों पर मरांडी ने कहा, इसका मतलब यह है कि वह (हेमंत) कह रहे हैं कि उनके विधायक 'बिकाऊ' हैं। यदि आप (हेमंत) सभी विधायकों को 'बिकाऊ' कहेंगे, तो कौन आपके साथ रहना चाहेगा। अगर कोई विधायक अपना दुख व्यक्त करता है, तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए। मरांडी ने कहा कि चंपई जैसे वरिष्ठ नेता के अलग होने से पार्टी (झामुमो) पर असर पड़ेगा। वही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपई सोरेन ने थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वे 30 अगस्त को

चम्पाई सोरेन (पूर्व मुख्यमंत्री)
मंत्री
जल संसाधन तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची।

झारखण्ड मंत्रालय
नेपाल हाऊस, भूतल आवंटित कमरा सं०-11, डोरण्डा, राँची। पिन-834002
आवासीय कार्यालय
बुटी रोड, आवास सं०-D2, मोराबादी, राँची। पिन-834008

पत्रांक 49/R/2024 दिनांक 28/8/2024

अध्यक्ष,
झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, राँची।

आदरणीय गुरु जी,
जोहार!

मैं चम्पाई सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा की वर्तमान कार्यशैली एवं नीतियों से विक्षुब्ध होकर, पार्टी छोड़ने को विवश हूँ।

अत्यंत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप के मार्गदर्शन में जिस पार्टी का सपना हम जैसे कार्यकर्ताओं ने देखा था, एवं जिस के लिए हम लोगों ने जंगलों, पहाड़ों एवं गांवों की खाक छानी थी, आज पार्टी अपनी उस दिशा से भटक चुकी है।

झामुमो मेरे लिए एक परिवार जैसा रहा एवं मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम की वजह से, मुझे बहुत ही पीड़ा के साथ यह कठिन निर्णय लेना पड़ा रहा है।

आपके वर्तमान स्वास्थ्य की वजह से, आप सक्रिय राजनीति से दूर हैं, तथा आपके अलावा पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं है, जहां हम अपनी मन की पीड़ा को बता सकें। इस वजह से, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता एवं सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं।

आपके मार्गदर्शन में, झारखण्ड आंदोलन के दौरान तथा उसके बाद भी, मुझे जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सदैव मेरे मार्गदर्शक बने रहेंगे।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें।

धन्यवाद!

भवदीय
28/8/24
(चम्पाई सोरेन)

रांची में आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे।

बहरहाल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के नेता चंपई सोरेन इस समय राज्य की राजनीति में अलग-थलग पड़ गए हैं। पिछले दिनों उनकी दिल्ली यात्रा भी बेअसर रही। वे इस दौरान भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं कर पाए। इससे पहले कहा गया था कि वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। चंपई ने यह भी कहा था कि वे राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया वे राजनीति से सन्यास नहीं लेंगे। भाजपा में जाने की अटकलें भी ठंडी पड़ गई हैं। चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वे नई पार्टी बना सकते हैं और उसी के बैनर तले विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। चंपई को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाना जाता है। यदि चंपई सोरेन झामुमो से बगावत कर नया दल बनाते हैं तो इसका सीधा फायदा भाजपा को ही मिलने वाला है। क्योंकि चुनाव में वे झामुमो के ही वोट काटेंगे। हालांकि उनके भाजपा में जाने की अटकलों पर विराम लग गया है। लेकिन, वे नई राजनीतिक पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। वर्तमान में चंपई झारखंड की सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। बताया जा रहा है कि यदि चंपई अलग दल बनाकर चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो वे कई सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन के बाद चंपई झारखंड में दूसरा बड़ा चेहरा है। उन्हें शिबू सोरेन का करीबी माना जाता है। उनकी वफादारी के चलते ही उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था।

पायलट बाबा का निधन, आश्रम में दी भू-समाधि

जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा को आज उनके आश्रम में भू समाधि दे दी गई है। पायलट बाबा ने बीती 20 अगस्त को मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में अंतिम सांस ली। जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को हरिद्वार आश्रम में दर्शन के लिए रखा गया। पायलट बाबा के अंतिम दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे अखाड़े से जुड़े पदाधिकारी, संत समाज और स्थानीय लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। पायलट बाबा श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर आध्यात्मिक गुरु भी थे। सामाजिक और पारिवारिक रूप से संन्यास लेने से पहले वे भारतीय वायुसेना में बतौर विंग कमांडर भी रहे। उन्होंने साल 1962, 1965, 1971 के युद्ध में बतौर विंग कमांडर हिस्सा लिया था। सैनिक से संत बने इस आध्यात्मिक गुरु की देश-विदेश में अपनी अनोखी साख रही है। पायलट बाबा के अध्यात्म और धार्मिक ज्ञान के चलते उनके बड़े संख्या में भक्त थे। भक्तों और अनुयायियों ने पायलट बाबा के देश से लेकर विदेश तक में कई आश्रम बना दिए हैं। पायलट बाबा का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नोखा बिशनपुर में 15 जुलाई 1938 को हुआ था। बाबा का मूल नाम कपिल सिंह था। गांव में शिक्षा-दीक्षा लेने के बाद उनका चयन इंडियन एयरफोर्स में हुआ। 1957 में भारतीय वायुसेना का कमीशन प्राप्त करने के बाद लड़ाकू विमान उड़ाना सीखा और वर्ष 1962, 1965, 1971 के युद्ध में

विंग कमांडर की भूमिका निभाई। विंग कमांडर से पायलट बाबा बनने का भी रोचक सफर है। इस विंग कमांडर ने महज 33 साल की उम्र में एयरफोर्स से रिटायरमेंट ले लिया और संन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे। बताया जाता है कि साल 1962 में जब विंग कमांडर कपिल सिंह उर्फ पायलट बाबा विमान उड़ा रहे थे तो विमान में तकनीकी गड़बड़ी हो गई, खराबी के चलते विमान की लैंडिंग नहीं कर पा रहे थे, तब पायलट बाबा ने अपने गुरु हरि बाबा का स्मरण किया। हरि बाबा को याद करते ही उन्हें लगा कि उनके गुरु कॉकपिट में बैठकर विमान को सुरक्षित लैंडिंग करवा रहे हैं। तब से उनका मन अध्यात्म से अधिक जुड़ गया। पायलट बाबा ने रिटायरमेंट लेने के बाद अपनी लग्जरी जिंदगी और सुविधाओं को त्याग कर संत समाज की राह को चुना। अध्यात्मिक जिंदगी जीते हुए वे सन् 1974 में जूना अखाड़ा से जुड़े, अखाड़े में उनकी धार्मिक शिक्षा-दीक्षा शुरू होने के साथ ही संत समाज में समागम हो गया। उन्हें सन् 1998 में महामंडलेश्वर पद मिला, वर्ष 2010 में उज्जैन के प्राचीन जूना अखाड़ा शिवगिरि आश्रम नीलकंठ मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। जूना अखाड़े

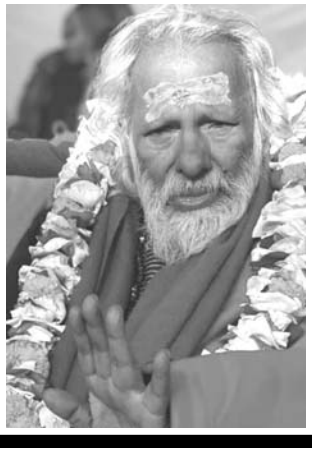

के महामंडलेश्वर पद पर रहते हुए पायलट बाबा ने 86 वर्ष की आयु में प्राण छोड़ दिए। वे काफी समय से गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे थे। बाबा के निधन का समाचार मिलते ही देश-विदेश में उनके भक्त शोक में डूब गए। हरिद्वार, उत्तरकाशी, नैनीताल और बिहार के सासाराम सहित नेपाल, जापान, सोवियत संघ सहित कई देशों में बड़ी संख्या में उनके अनुयायी आश्रम में रहते हैं। पायलट बाबा ने निधन से पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। उनके पास अकूत संपत्ति है। पायलट बाबा की मौत के बाद प्रश्न उठता है कि इस संपत्ति का वारिस कौन होगा, उनकी विरासत कौन संभालेगा? हालांकि जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरि का कहना है कि जूना अखाड़े के जिस संत के पास दो तिहाई मत होगा, वह ही बाबा का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा।

Mob stuffs red chilli powder in youth's private part

In a shocking incident, a man was subjected to brutal punishment after being caught on suspicion of theft in Bihar. A mob stuffed red chili powder to his private part. A disturbing video of this incident is going viral on social media. The incident took place in Araria, where the youth was captured on suspicion of car theft and publicly punished in a brutal manner. The viral video shows a man with his hands tied behind his back. A person opens a packet of red chili powder and inserts it on his rectum. Another person can also be seen in the video using a pen to forcibly stuff the chili powder into the man's anus. After stuffing the chili powder into his buttocks, they pull his pants back up while he continues to cry in pain. The video is going viral on social media, with netizens demanding strict action against those involved in this inhuman act. Reacting to the viral video, Araria police said on X that the inhuman act was committed with the youth caught on charges of theft and one of the accused has been arrested in the matter. "This case is related to Araria police station area. This inhuman act was committed with a youth caught on charges of theft. One of the accused who committed the above act has been arrested. Further action is being taken regarding others," Araria police wrote on X.

Begusarai Deputy Municipal Commissioner runs away with niece after 10 years of affair, family accused him of kidnapping

Deputy Municipal Commissioner of Begusarai Municipal Corporation of Bihar is reportedly absconding with his niece and girl's family has accused him of kidnapping her. Shiv Shakti Kumar and Sajal Sindhu are residents of the same village in Hajipur and are reportedly in love relationship for the last 10 years. On August 12, Sajal went to the Deputy Municipal Commissioner's office with a boy. After this, she did not return to home. The family then registered a kidnapping case against Kumar in Hajipur police station. The girl's family said that Deputy Municipal Commissioner Shiv Shakti Kumar is Sajal's uncle. The girl's uncle Arun Kumar wrote a letter to the Mayor and the Municipal Commissioner that Shiv Shakti Kumar is his cousin and has kidnapped his niece Sujal. Meanwhile, a video of both of them has surfaced on the social media. In the 19-second video, the girl says, "We both love each other for the last 10 years. It is my right to marry the boy of my choice."

खेत में बने वायरल पुलों की असली कहानी क्या है?

● सीटू तिवारी

बिहार अलग-अलग वजहों से देशभर में सुर्खियों में रहता है। हाल के दिनों में एक के बाद एक कई 'गिरते हुए पुल' देशभर में चर्चा का विषय बने थे। ऐसे पुलों का वीडियो भी खूब वायरल हुआ। इन सबके बीच बिहार में कुछ ऐसे भी पुल हैं, जो 'अजूबे' के तौर पर देखे जाने लगे हैं। हाल ही में बिहार के अररिया का ऐसा ही पुल चर्चा में आया। बीबीसी ने इसके और ऐसे ही कुछ और पुलों के बनने और फिर 'वायरल' हो जाने की कहानी जानी है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 350 किलोमीटर दूर अररिया के रानीगंज प्रखंड (ब्लॉक) का परमानंदपुर गाँव। घनी आबादी वाले इलाके से जैसे ही आप खेतों की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ आपको खेत में खड़ा एक पुल दिखाई देगा।

ये वही पुल है, जिसकी हम बात कर रहे थे। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर 'खेत के बीच बने अजूबा पुलश के तौर पर मशहूर हुआ। पानी से भरे खेतों से होते हुए जब आप पुल के पास पहुँचेंगे, तो उसके नीचे से नदी की धारा बहती दिखेगी। ये दुलारदई नदी है, जिस पर पुल परमानंदपुर के ग्रामीणों की मांग के बाद बनाया गया था। गाँव के युवा संजय कुमार मंडल बीबीसी को बताते हैं, हम लोग चार साल से दो पुल का डिमांड सरकार से कर रहे थे। सरकार ने इस साल जनवरी में एक पुल बना दिया लेकिन पुल पर चढ़ने के लिए सड़क ही नहीं बनाई। कोई कैसे चढ़ेगा? सरकार हम लोगों को ओलंपिक की ट्रेनिंग दे दे।'

क्या है वायरल पुल की कहानी?

दरअसल, ये पुल जहां बना है, वो पूरा इलाका परमानंदपुर गाँव के लोगों की खेती की जमीन है। इन्हीं खेतों के बीच से दुलारदई नाम की नदी बहती है। ग्रामीणों को आने-जाने के साथ साथ ट्रैक्टर आदि वाहन ले जाने में दिक्कत होती थी। इसलिए पुल बनाने की मांग हो रही थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3।20 करोड़ की लागत से परमानंदपुर लक्ष्मी स्थान से कुपारी बॉर्डर तक सड़क बनने की योजना साल 2023 में बनी। ये पुल इसी 3।20 किलोमीटर लंबी सड़क का हिस्सा है। ग्रामीण कार्य विभाग के फारबिसगंज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रवीण कुमार बीबीसी से बताते हैं, "ये पुल इसी साल अप्रैल माह में बन गया था और जब बना तो ग्रामीणों ने सहयोग दिया। लेकिन जब पुल के पहुंच पथ (एप्रोच) बनाने के लिए जेसीबी से मिट्टी गिराई जाने लगी तो असामाजिक तत्वों ने निजी जमीन बताकर काम में बाधा डाली।"

क्या कहते हैं गाँव वाले

परमानंदपुर गाँव वाले दो बातें कहते हैं। पहला तो ये कि पुल का निर्माण जनवरी 2024 में शुरू हुआ और इसी महीने पूरा हो गया। दूसरा ये कि ग्रामीणों को एप्रोच रोड बनाने के लिए निजी जमीन देने के लिए सरकार ने संपर्क नहीं किया। दरअसल पुल का ढांचा और एक तरफ की एप्रोच रोड तो सरकारी जमीन पर है। लेकिन दूसरी तरफ की एप्रोच रोड में अर्जुन मंडल और उदयकांत झा नाम के दो ग्रामीणों की जमीन आती है। उदयकांत झा की दो डेसीमल से ज्यादा जमीन इस एप्रोच रोड में आ रही है। वो बताते हैं, "मुझसे सात अगस्त 2024 से पहले तक किसी अधिकारी ने जमीन के लिए संपर्क ही नहीं किया। जब न्यूज आई तो सीओ (अंचलाधिकारी) साहब ने बुलाया। हमको सरकार मुआवजा दे दे, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी देगी तो हम जमीन दे देंगें।" इस बीच ये सवाल अहम है कि क्या योजना का डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता? इस सवाल के जवाब में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रवीण कुमार कहते हैं, "ये बहुत छोटी सी बात है। योजनाओं में ऐसा होता है और इन मामलों को बाद में

सुलझा लिया जाता है।"

यहां आदमी की जान की कोई वैल्यू है?

पुल की तस्वीर वायरल होने के बाद सरकारी जमीन वाले हिस्से की एप्रोच रोड पर मिट्टी भराई का काम शुरू हो गया है। यानी ग्रामीण एक तरफ से पुल पर इस मिट्टी के सहारे चढ़ जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ उतरने के लिए उन्हें पुल से कूदना पड़ता है। भारी सामान लिए ग्रामीण दुलारदई नदी से ही पार होते हैं। जिसमें अभी पानी उनकी कमर से ऊपर तक आता है। बारिश ज्यादा होने की सूरत में ये नदी पार करना भी मुश्किल होगी। कल्पना देवी अपनी भैंसों को चराने के लिए पुल के पास आई है। वो कहती हैं, "ये पुल थोड़ी बारिश में ही गिर जाएगा। सरकार ने पुल बना दिया और रोड दी ही नहीं। पानी में चलते-चलते पाँव पक गए।" पुल पर चढ़ने के लिए लोगों को बेहद मुश्किल से चढ़ना पड़ता है जो किसी दीवार पर चढ़ने जैसा है। बुजुर्ग पुरूषों से लेकर बच्चे ऐसे ही चढ़ते हैं। अपने जीवन के 70 बसंत देख चुके जोगिंदर मंडल कहते हैं, "यहाँ के आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं है। यहां पुल बनने से ये खतरनाक जगह हो गई है। पुल बनेगा नहीं तो आदमी ऐसे ही जाते रहेगा, मरता डूबता रहेगा। पुल बस टांग दिया है सरकार ने।"

अररिया में और भी हैं ऐसे पुल

अररिया जिले में ऐसे और भी पुल हैं, जिनमें कई साल बीत जाने के बाद एप्रोच रोड ही नहीं बनी है। जिले के पलासी प्रखंड (ब्लॉक) से कघ्रीब 20 किलोमीटर दूर ब्रहमकुंभा पंचायत में ऐसा ही पुल है। ब्रहमकुंभा पंचायत के बेलपरा वॉर्ड नंबर 4 में बकरा नाम की नदी की धार पर ऐसा ही एक पुल बना है। ये पुल जुलाई 2021 में बनना शुरू हुआ था और जुलाई 2022 में बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इस पुल में भी कोई एप्रोच रोड नहीं है। यानी पुल पर चढ़ने का रास्ता गायब है। इस पुल के आसपास जमा मिट्टी और कुछ कूद-फांद कर लोग

चढ़ते उतरते हैं। पुल पर लोग साइकिल हाथ में उठाकर चढ़ाते है या पैदल चढ़ते हैं। पुल पार कर रही शोभा देवी कहती हैं, "चढ़ाई उतराई में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। रोड बन जाती तो परेशानी नहीं होती। सरकार पैसा देती है कि पुल बनाओ, रास्ता बनाओ लेकिन पब्लिक को तो कुछ मिलता नहीं है।" वहीं मोहम्मद गुड्डू कहते है, "बहुत सारे लोगों के घर में मोटरसाइकिल है, गाड़ी है लेकिन पुल पर चल ही नहीं सकते।" इसी तरह का पुल अररिया के कुर्साकांटा ब्लॉक के कुआरी बाजार के पास है। ये पुल मसना नाम की नदी पर बना है। इस पुल की ऊँचाई इतनी ज्यादा है कि इस पर लोगों का चढ़ना मुश्किल है। पुल के बारे में मोहम्मद शहाबुद्दीन बताते हैं, "नया पुल जो बना है। उस पर कोई चढ़ ही नहीं सकता। लोग नीचे से ही पानी पार करके आते जाते हैं।"

बिना एप्रोच रोड वाले पुल-पुलिया की सूची मांगी गई : डीएम

ये पुल पहसी, ललोखर, कुआरी, कुर्साकांटा को जोड़ता है। ललोखर पंचायत के मुखिया मकतूब आलम बताते है कि ये पुल साल 2017 से ऐसे ही बना पड़ा है। वो बताते है, " ये पुल बिहार सरकार ने बनवाया। हम लोग नेपाल के पास है तो बाद में इस रोड को बार्डर रोड बना दिया। अब कुछ हो ही नहीं रहा। हम लोग एमपी, एमएलए, डीएम सब से कह चुके है। बारिश ज्यादा होगी तो सारा संपर्क टूट जाएगा। नदी पार करना मुश्किल होगा।" अररिया की डीएम इनायत खघन इस बारे में कहती हैं," हम लोगों ने अररिया और फारबिसगंज डिवीजन के कार्यपालक अभियंताओं से ऐसे सभी पुल-पुलिया की सूची मांगी है जिसमें एप्रोच रोड नहीं बनी है। ये सूची मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।"

बिहार सरकार की ग्रामीण कार्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्र में बारहमासी सड़कों के जुड़ाव वाले राज्यों में बिहार पिछड़ा राज्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के मुताबिक साल 2005 -06 से सितंबर 2023 तक ग्रामीण कार्य विभाग ने 1910 पुलों का निर्माण किया गया है बिहार की 85 फीसदी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। ऐसे में ये देखना जरूरी है कि सरकारी दावों से इतर इस ग्रामीण आबादी के लिए बने ये पुल कितने जन उपयोगी हैं।

पुल गिरने की घटनाएँ

बिहार में पिछले दिनों कई पुल गिरने से सरकार की किरकिरी हुई है। 18 जून से 6 जुलाई, 2024 के बीच बिहार में पुल गिरने की 13 घटनाएं हुई थीं। इसमें सिर्फ गंडकी नदी पर 7 पुल गिरे थे। जिसके बाद बिहार सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसे इंजीनियरों की लापरवाही माना है। दरअसल सिवान, सारण और गोपालगंज में बहने वाली गंडकी नदी (इसे छाड़ी नदी भी कहते है) में नदी जोड़ परियोजना के तहत गाद निकासी का काम होना था। इससे पहले अररिया जिले में बकरा नदी पर गिरे पुल की जांच के लिए बिहार अभियंत्रण सेवा संघ ने भी दो सदस्यीय जांच टीम गठित की थी। इस जांच दल ने पुल की डिजाइनिंग, बिल्डिंग मैटेरियल, सराउंडिंग आदि पक्षों पर जांच की है। संघ के महासचिव राकेश कुमार ने बीबीसी को बताया कि बकरा नदी पर गिरे पुल की जांच में दो वजहे निकली हैं। पहला तो ये कि पुल की नींव के पास बालू उत्खनन हुआ और दूसरा ये कि डिजाइनर ने नदी की धारा बदलने की प्रवृति को पुल डिजाइनिंग में ध्यान नहीं रखा। इस मामले में जांच दल ने अनुशंसा की है। राकेश कुमार बताते हैं, 'सरकार ने जब पुल निर्माण निगम बनाया है तो ग्रामीण कार्य विभाग सहित जो विभाग पुल बनाते है, उनको पुल निगम के एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। दूसरा ये कि परामर्शी सेवाए जो सरकार बाहर से ले रही है वो बाहर या मार्केट से नहीं लेकर खुद के विभागीय इंजीनियर को ही ट्रेनड करना चाहिए।' बिहार में पुल निर्माण की जिम्मेदारी पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग सहित कई विभागों की है।

Ram Mandir float in NYC's India Day parade stirs controversy

A carnival float depicting Ayodhya's Ram temple planned for an upcoming India Day parade in the streets of New York City has sparked criticism, with several groups calling it "anti-Muslim." The float depicts the Ram Mandir — a grand pink sandstone temple built for the Hindu god Ram, in the holy city of Ayodhya. The temple was built on top of the ruins of the 16th-century Babri mosque, which was destroyed by Hindu nationalist mobs in 1992. Consecrated and opened in January 2024 by Indian Prime Minister Narendra Modi, the temple remains a controversial topic and a bitter reminder of the communal bloodshed in 1992 for some.

What did the groups say?

The Council on American Islamic Relations, Indian American Muslim Council and Hindus for Human Rights were among groups that signed a letter to New York City Mayor Eric Adams and New York Governor Kathy Hochul, saying that the float glorified the mosque's takedown. "This float's presence represents these groups' desire to conflate Hindu nationalist ideology with Indian identity, but India is a secular country," the letter said. "This is not merely a cultural display, but a vulgar celebration of anti-Muslim heat, bigotry, and religious supremacy." On the other hand, the Hindu American Foundation said it was an exercise of free speech.

Meanwhile the Federation of Indian Associations — the group that is organizing the event — said the float celebrated the inauguration of a landmark significant to Hindus.

It also said the parade represents the country's diversity and will feature floats from various communities in India.

What did the mayor say?

Mayor Adam's office, earlier this week, said there was "no room for hate" but that the US Constitution's First Amendment right to free speech prevented the city from withdrawing the permit or ordering changes to the float. His office later said he did not plan on attending the event, despite having done so in the last few years. The India Day parade in NYC has been taking place every year for over four decades, to mark the celebration of India's independence from the British on August 15, 1947.

सरकार से कर्मचारी लंबे समय से न्यू पेंशन स्कीम को हटाकर पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाने की मांग कर रहे थे लेकिन मोदी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लांच कर दी। यह पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। इससे सीधे तौर पर केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि बेसिक सैलरी की 50 फीसदी राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। हालांकि इसके लिए 25 साल की नौकरी जरूरी होगी। 10 साल काम करने वालों को 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। सरकार की घोषणा के मुताबिक फैमिली पेंशन के रूप में 60 फीसदी राशि ही मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति को 20 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलते हैं, तो उसके बाद पत्नी को 12 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। बता दें कि ओपीएस में कर्मचारियों को योगदान नहीं देना होता था। एनपीएस में कर्मचारियों को 10 प्रतिशत योगदान देना होता है। यूपीएस में भी एनपीएस की तर्ज पर ही कर्मचारियों को 10 प्रतिशत योगदान देना होगा। यूपीएस के लिए कर्मचारियों को कोई भी अतिरिक्त योगदान नहीं देना होगा, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन फंड में योगदान मौजूदा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया गया है। यह साल दर साल महंगाई दर आदि के कारण बढ़ता रहेगा। इससे केंद्र पर वर्ष 2025-26 के दौरान ही 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ओपीएस में फिक्स पेंशन मिलती थी, एनपीएस में फिक्स पेंशन नहीं मिलेगी। यूपीएस में एनपीएस की तरह फिक्स पेंशन मिलेगी। न्यूनतम 10 साल की नौकरी पर कम से कम 10 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी। सरकार का मानना है कि अभी कार्यरत 99 प्रतिशत से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों के लिए एनपीएस से ज्यादा यूपीएस आर्थिक तौर पर फायदेमंद होगा। एनपीएस वर्ष 2004 से लागू है और तब से अभी तक जितने सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको यूपीएस के तहत पेंशन सुविधा लेने का विकल्प मिलेगा। अगर कर्मचारी ऐसा करते हैं तो उन्हें जो अतिरिक्त राशि व उसका ब्याज बनेगा, उसका भुगतान केंद्र से होगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों के पास विकल्प होगा कि वह पुरानी स्कीम एनपीएस में ही रहें या फिर नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को चुनें। मोदी सरकार की इस पेंशन स्कीम में ऐसे कई फायदे हैं, जो कर्मचारियों की लाइफ रिटायरमेंट के बाद आसान बना सकती है। मसलन 25 साल नौकरी के बाद बेसिक सैलरी की 50 फीसदी पेंशन, 10 साल नौकरी के बाद 10 हजार रुपये पेंशन जैसे प्रावधान हैं। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर्स को भी उम्मीद जगी है कि उन्हें भी इस स्कीम का फायदा मिलेगा। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने योजना और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को लेकर कुछ नहीं कहा है। लेकिन आगे चलकर निजी सेक्टर को इसमें शामिल किया जा सकता है। एनपीएस को साल 2004 में लागू किया गया था। उस समय भी यह स्कीम यूपीएस की तरह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही थी। मगर कुछ साल बाद 2009 में निजी सेक्टर को भी इसमें शामिल कर लिया गया। यह सुपरहिट साबित हुआ। साल दर साल इसमें बढ़ोतरी होती चली गई। हर साल इसमें 28 फीसदी से भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। इस साल जुलाई में एनपीएस असेट्स में 39 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई और यह 2.59 लाख करोड़ की संपत्ति बन गई। हर साल इसमें 9

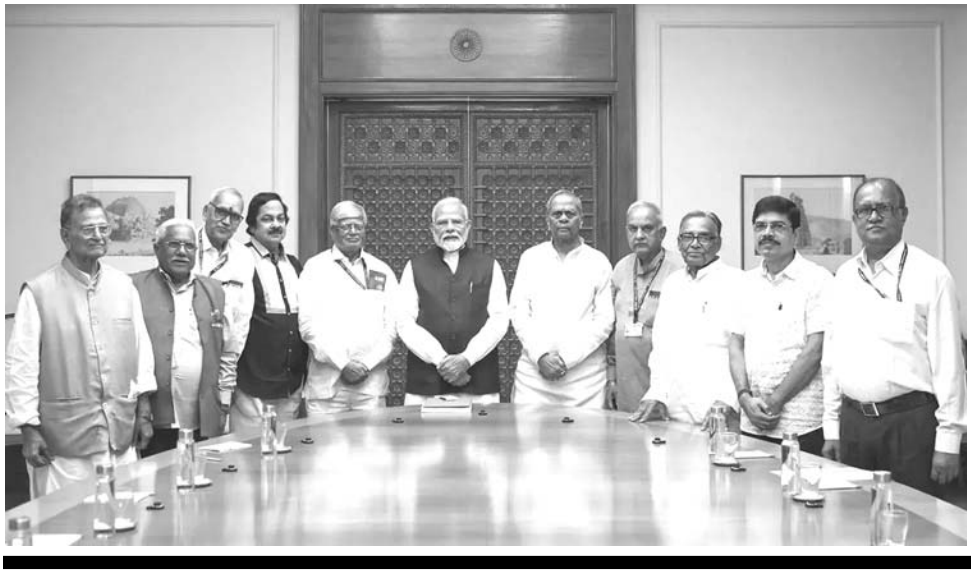

मंत्रिमण्डल

कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी

Posted On: 24 AUG 2024 8:33PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है।

एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. **सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।**
2. **सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत।**
3. **सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह।**
4. **महंगाई सूचकांक: सेवा कर्मचारियों के मामले में सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर**

औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत

5. **ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान**

सेवा के प्रत्येक छह महीने पूरे होने पर सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा

इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी

****

एमजी/एआर/एसकेएस/डीवी

(Release ID: 2048627) Visitor Counter : 7587

Read this release in: Odia , English , Khasi , Urdu , Marathi , Bengali-TR , Bengali , Assamese , Manipuri , Punjabi , Gujarati , Tamil , Telugu , Kannada , Malayalam

लाख से ज्यादा प्राइवेट कर्मचारी जुड़ते चले गए। पिछले महीने तक करीब 58 लाख कर्मचारी निजी सेक्टर से ही थे। ऐसे में इस स्कीम को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए हो सकता है कि जल्द ही इसे निजी सेक्टर में भी लागू कर दिया जाए। बता दें कि एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) एक स्वैच्छिक योजना है, जिसमें 18-60 आयु वर्ग के सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को कवर किया जाता है। बुढ़ापे में भी नियमित आय होती रहे। कर्मचारी की जिंदगी आराम से कट जाए, इसकी चिंता सरकार को होती है। चाहे व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। बुजुर्गों की जिम्मेदारी समाज के साथ सरकार की होती है। सरकार ने उनके प्रयास के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं। नेशनल पेंशन योजना उसी का हिस्सा है। जिसमें व्यक्ति को 60 वर्ष पूरे होने के बाद संरक्षित आय का हिस्सा मिलना शुरू होता है। एनपीएस योजना में दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं।

टियर वन और टियर टू :-

टियर वन :- कर्मचारी 60 वर्ष की आयु तक पैसा नहीं निकालते हैं। जिसके बाद शेष जिंदगी के लिए उनको पेंशन प्रदान की जाती है।

टियर टू :- यह एक स्वैच्छिक बचत खाता है। जिसमें कर्मचारी जब चाहे पैसा निकाल सकता है। लेकिन यह खाता खोलने से पहले टियर वन का सक्रिय खाता होना जरूरी होता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कर्मचारी को लाभ लेने के लिए सीआरए की ओर खोले गए सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के बारे में सूचित किया जाता है। इसके बाद कर्मचारी अपने चुने पीओपी-एसपी के माध्यम से अपना सदस्यता शुल्क जमा करना शुरू करता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कर्मचारी को लाभ मिलना शुरू हो जाता है।

उल्लेखनीय है कि विपक्ष ओल्ड स्कीम का मुद्दा बार-बार उठाता रहा है। कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने अपने पार्टी घोषणा पत्र में ओल्ड स्कीम लागू करने की घोषणा की है। वैष्णव ने कहा कि विपक्ष ओपीएस पर सिर्फ राजनीति करता है। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों से पहले, सरकारी कर्मचारियों की काफी समय से लंबित मांगों को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी गई, जिसमें सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए गरिमा व आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है तथा यह उनके कल्याण एवं सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सेवा में शामिल होने वाले 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित रूप से

UPS को लेकर 10 बड़ी बातें, जानिये कैसे होगा लागू, किसे होगा फायदा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी। यह 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। UPS को 10 बिंदुओं के माध्यम से समझें। किसे मिलेगा फायदा और क्या होंगे नियम।

☞ **सुनिश्चित पेंशन :-** सेवानिवृत्त व्यक्तियों को अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते कि उन्होंने 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा की हो। कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक।

☞ सरकार अपना अंशदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर रही है। कर्मचारियों का अंशदान नहीं बढ़ेगा।

☞ **सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन :-** किसी पेंशनभोगी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, उसके परिवार को कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60% प्राप्त होगा।

☞ **सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन :-** न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर पेंशन के रूप में 10,000 रू० प्रति माह।

☞ **मुद्रास्फीति संरक्षण :-** पेंशन को मुद्रास्फीति के अनुसार अनुक्रमित किया जाएगा। महंगाई राहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित होगी, जैसा कि सेवारत कर्मचारियों के मामले में होता है।

☞ ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान। सेवा के प्रत्येक पूर्ण छः माह के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा।

☞ यूपीएस के प्रावधान एनपीएस के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों (जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं) पर लागू होंगे। पिछली अवधि के बकाया का भुगतान पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ किया जाएगा।

☞ यूपीएस कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा। मौजूदा एनपीएस/वीआरएस के साथ-साथ एनपीएस के साथ-साथ भविष्य के कर्मचारियों के पास यूपीएस में शामिल होने का विकल्प होगा। एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा।

☞ यूपीएस का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इससे लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने के लिए भी यही संरचना तैयार की गई है।

☞ यदि राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं, तो इससे 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है, जो वर्तमान में एनपीएस पर हैं।

वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिए जाने को मंजूरी देने के बाद यह टिप्पणी की। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक अप्रैल, 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। यह पेंशन योजना, एनपीएस से पहले के कर्मचारियों के लिए लागू परिभाषित लाभ के बजाय योगदान के आधार पर लाभ देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर लिखा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा से लौटने के बाद यहां केन्द्रीय कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जिसमें कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के विकल्प के तौर पर एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस पर सहमति बनी।

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी ओल्ड पेंशन स्कीम बड़ा मुद्दा थी और चुनाव में कांग्रेस को इसका सीधा फायदा मिला था। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या यूनीफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की नाराजगी दूर कर पाएगी। इसको लेकर ओपीएस की बहाली को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चला रहे है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु कहते हैं कि यूनीफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) कर्मचारियों के साथ धोखा है और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर उनकी लड़ाई जारी रहेगी। वह कहते हैं कि नेंशल पेंशन स्कीम और यूनीफाइड पेंशन स्कीम दोनों खराब है और कर्मचारियों के हित में नहीं है इसलिए हमारी लड़ाई ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जारी

यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS), राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), और पुरानी पेंशन योजना (OPS). यहाँ UPS, NPS, और OPS का एक त्वरित तुलना दी गई है:

विशेषता	यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS)	राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)	पुरानी पेंशन योजना (OPS)
पेंशन प्रकार	निर्धारित लाभ (गारंटीकृत पेंशन राशि)	निर्धारित योगदान (बाजार आधारित, कोष आधारित)	निर्धारित लाभ (गारंटीकृत पेंशन राशि)
पेंशन राशि	सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50%	बाजार आधारित, संचित कोष पर आधारित	अंतिम निकाले गए मूल वेतन का 50%
गारंटीकृत रिटर्न	हाँ	नहीं	हाँ
मुद्रास्फीति अनुक्रमण	हाँ (पेंशन मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित)	नहीं	हाँ (मुद्रास्फीति अनुक्रमण द्वारा समायोजित)
एकमुश्त भुगतान	हाँ (प्रत्येक 6 महीनों की सेवा के लिए मासिक वेतन का 1/10वां हिस्सा)	हाँ (कोष प्रदर्शन पर निर्भर)	कोई एकमुश्त भुगतान नहीं; मासिक पेंशन पर ध्यान केंद्रित
पारिवारिक पेंशन	कर्मचारी की पेंशन राशि का 60%	संचित कोष और चुने गए विकल्प पर निर्भर	कर्मचारी की पेंशन राशि का 60%
न्यूनतम पेंशन	कम से कम 10 वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए ₹10,000 प्रति माह	कोई न्यूनतम पेंशन नहीं	कोई न्यूनतम पेंशन नहीं, लेकिन सामान्यतः तय फॉर्मूला के कारण अधिक मानी जाती है
सरकारी योगदान	गारंटीकृत पेंशन की ओर सरकारी योगदान	मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 10% (केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 14%)	पूरी तरह से सरकारी वित्त पोषित
लचीलापन	सीमित लचीलापन; गारंटीकृत लाभों पर ध्यान केंद्रित	निवेश विकल्पों में उच्च लचीलापन	कोई लचीलापन नहीं; तय लाभ
जोखिम कारक	कम जोखिम (गारंटीकृत रिटर्न)	उच्च जोखिम (बाजार आधारित रिटर्न)	कम जोखिम (गारंटीकृत रिटर्न)

रहेगी। वह कहते हैं कि हमें इन सुधारों और संशोधनों पर कोई विश्वास नहीं है। कर्मचारी नेता विजय कुमार बंधु कहते हैं कि जो कर्मचारी नेता यूपीएस का समर्थन कर रहे है वह सब ओपीएस ले रहे है और ऐसे में वह कही न कही ओपीएस को लेकर चल रही हमारी लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश कर रहे है। वह कहते हैं कि एक भी कर्मचारी जो NPS ले रहा है वह यूपीएस का समर्थन में नहीं है। विजय कुमार बंधु कहते हैं अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वह अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में हड़ताल पर जाने जैसा बड़ा फैसला करेंगे। वहीं में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे है वहां पर वह वोटर फॉर ओपीसी की मांग को लेकर जनता के बीच जाएंगे और इसको लेकर अभियान चलाएंगे। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के इस कदम की तारीफ भी कर्मचारी संगठन के नेता कर रहे है। रेलवे कर्मचारी संगठन एआईआरएफ के महासचिव और कर्मचारी नेता शिव गोपाल मिश्रा कहते हैं कि यूपीएस का विरोध करने वाले अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते विरोध कर रहे है और वह इसका विरोध कर इस पर राजनीति करना चाह रहा है। वह एनपीएस की तुलना में यूपीएस का बेहतर बताते हुए कहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में मूल अंतर ये है कि ओपीएस नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी थी और एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूटरी है। इसमें 10 प्रतिशत कर्मचारी का भी कटेगा, ये पहले भी कटता था, लेकिन यह ब्याज के साथ रिटर्न हो जाता था। वह आगे कहते है कि यूपीएस में कर्मचारियों को वेतन का 50 फीसदी देने का एलान करने के साथ उनकी पेंशन को सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ इसमें महंगाई राहत भी दिया जाएगा। जिससे कर्मचारी रिटायरमेंट के समय पैसे मांगने के लिए मजबूर नहीं होंगे और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वह कहते हैं कि एनपीएस किसी भी नजरिए से कर्मचारियों के हित में नहीं थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा। अब तक उनकी पेंशन शेयर बाजार और बाजार की अटकलों पर निर्भर थी। मिश्रा ने कहा कि अब से कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर उनके आखिरी वेतन का आधा हिस्सा मिलेगा, साथ ही डीए का लाभ भी मिलेगा।

बहरहाल, कांग्रेस ने एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा को लेकर केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एकीकृत पेंशन योजना में 'यू' का मतलब मोदी सरकार का 'यू-टर्न' है। कांग्रेस का यह कटाक्ष ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन की गारंटी को मंजूरी दी थी। सरकार पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन

खरगे ने कहा कि यूपीएस में 'यू' का मतलब मोदी सरकार का 'यू-टर्न' है। 4 जून के बाद जनता की शक्ति प्रधानमंत्री के सत्ता के अहंकार पर हावी हो गई है। खरगे ने कहा कि दीर्घ अवधि के पूंजीगत लाभ/सूचकांककरण के बारे में बजट में कदम वापस लिया, वक्फ विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया, प्रसारण बिल और लेटरल एंट्री वापस ली गई। कांग्रेस प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, ''हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाएंगे!'' उन्होंने कहा कि इस वैकल्पिक योजना से 23 लाख केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और यदि राज्य सरकारें इस योजना में शामिल होती हैं, तो यह संख्या 90 लाख तक बढ़ सकती है। दरअसल, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद होने के बाद से लागू न्यू पेंशन स्कीम से कर्मचारी खुश नहीं थे और लंबे समय से इसका विरोध कर रहे थे। सरकार ने जब यूपीएस लेकर आई है तो भी कई कर्मचारी इसका भी विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग थी कि उसे रिटायरमेंट पर 50 प्रतिशत बेसिक सेलरी और डीए अलाउंस के बराबर पेंशन मिले, न कि कंट्रीब्यूशन को घटाया या बढ़ाया जाए। हमारा पैसा, रिटायरमेंट पर बिल्कुल जीपीएफ की तरह ही हमें वापस कर दिया जाए। सरकार, नई व्यवस्था में सारा पैसा ले लेगी। लंबे समय तक पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने वाले नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि सरकार ने यूपीएस लाकर कर्मचारियों के साथ छल किया है।

27 Indians killed in Nepal bus accident

A bus carrying 43 Indian tourists veered off a mountain road and plunged down a steep cliff in Tanahun district of Nepal on Friday, killing 27 of them. Prime Minister Narendra Modi has expressed sadness at the accident and extended condolences to the bereaved families.

In a post on X, the PM said :- "Saddened by the loss of lives due to a road mishap in Tanahun district, Nepal. Condolences to the bereaved families. May the injured recover at the earliest. The Indian Embassy is providing all possible assistance to those affected."

The bus was en route to Kathmandu from Pokhara, and carried 43 people, all Indian nationals, including the driver and his assistant. While 27 of the passengers are confirmed dead the remaining are undergoing treatment in Kathmandu and a local hospital in Tanahun, media reports said. The bus, bearing the Indian registration number UP 53 FT 7623, reportedly lost control near Aina Pahara and veered off the road, tumbling 150 meters down a steep cliff before coming to a halt on the bank of river Marsyangdi in Abu Khaireni of Tanahun district. The top of the bus was completely destroyed during the fall, and the bus was severely damaged when it reached the riverbank. The bus had entered Nepal from the Belahiya checkpoint in Rupandehi district on Au-

gust 20 with an eight-day route permit, according to police, Himalayan Times reported. The Indian Ministry of External Affairs spokesperson said in a post on X that the Indian Embassy is extending all possible help in the matter. "We are deeply pained by the tragic death of 27 Indian nationals in a road accident in Tanahun district of Nepal. "We convey our deepest condolences. Our Embassy is extending all possible help in the matter. 16 people who were injured in the accident have been airlifted and are presently undergoing treatment in a hospital. "Embassy has set up emergency helpline numbers for affected families to reach out for assistance. They are in constant touch with local authorities and with affected families and are making arrangement for early transportation of mortal remains to India. Embassy would be giving regular updates on the matter. Embassy helpline numbers (24 x 7) are below: +977-9851107021 +977-9851316807 +977-9749833292 (all numbers on WhatsApp as well)"

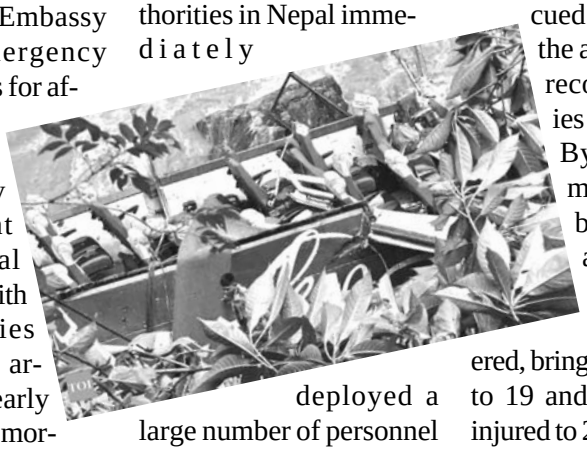

Following the report of the incident, authorities in Nepal immediately deployed a large number of personnel from the Armed Police Force, including 10 divers, Nepal Police, and the Nepali Army, to the accident site. However, the steep terrain made it difficult for rescuers to reach the crashed bus and carry out the rescue operation. In the initial stages, the rescue personnel had rescued 16 people from the accident site and recovered 14 bodies of the deceased. By 4:25 PM, six more people had been rescued, and five additional bodies were recovered, bringing the death toll to 19 and the number of injured to 22. However, the toll continued to rise as six of the injured receiving treatment at Abu Khaireni Hospital succumbed to their injuries, along with one person in Bharatpur Hospital and another at the accident site, bringing the total number of fatalities to 27, with 16 others still injured. Initially, twelve of the injured were airlifted to Kathmandu's Tribhuvan University Teaching Hospital for further treatment, while four others at the Abu Khaireni Hospital were flown later in the evening. This bus accident on the Nepali highways comes on the heels of the July 12 incident, where two passenger buses carrying 51 passengers were swept away by a landslide into the Trishuli River in the Simaltal area along the Narayanghat-Mugling road section in Chitwan district.

DSP Dipak Kumar Raya, spokesperson for the District Police Office in Tanahun, said the accident occurred at around 11:30 am. "The passenger bus fell from Aaina Pahara, Anbu Khaireni-2, into the Marsyangdi River," DSP Raya said. The passengers on the ill-fated bus were part of a larger group of 104 Indian pilgrims from Bhusal village in Jalgaon district of India's Maharashtra State. They had arrived in Nepal two days earlier for a 10-day tour, MyRepublica reported. The group, traveling in three buses, had reached Pokhara on August 21 and stayed there at Hotel Sports Nepal for two days before heading to Kathmandu on Friday morning. Tragically, one of these buses met with an accident, according to police officials. Madhav Prasad Paudel, chief of the Armed Police Force (APF) Battalion in Kurintar, said that most of the passengers traveling in the three buses were families and relatives. Those confirmed dead till Friday evening include 15 females and 11 males, at Anbu Khaireni Hospital. Similarly, one child died at a Chitwan-based hospital, according to Chief District Officer of Tanahun, Janardan Gautam.

Among the survivors, 12 injured passengers were airlifted by a Nepali Army helicopter to Kathmandu later in the afternoon. They are currently receiving treatment at the TU Teaching Hospital in Maharajgunj. The army helicopter continued to shuttle between the accident site and Kathmandu to transport the injured and provide medical assistance.

IAF, Army conduct first-ever para-drop of world's first portable hospital at 15,000 feet

Indian Air Force (IAF) and Indian Army have jointly carried out a first-of-its-kind precise para-drop operation of the Aarogya Maitri Health Cube at a high-altitude area close to 15,000 feet. These critical trauma care cubes have been indigenously developed under Project BHISHM (Bharat Health Initiative for Sahyog Hita and Maitri), an official statement said. The IAF utilised its advanced tactical transport aircraft C-130J Super Hercules, to airlift and precisely para-drop the cube. The Indian Army's Para Brigade, known for its operational acumen and agility, played an instrumental role in the successful deployment of the trauma care cube, utilising their advanced precision drop equipment. The operation was conducted in line with the government's vision of providing critical supplies to Humanitarian Aid and Disaster Relief (HADR) affected areas. This demonstration underscored the capability of such specialised military assets to effectively support HADR operations, even in the most remote and mountainous regions. The successful para-drop and deployment of the BHISHM trauma care cube exemplified the synergy and jointness of the Armed Forces and underscored the commitment to providing timely & effective assistance as first responders.

Ministry of Home Affairs creates 5 new districts in Ladakh

The Ministry of Home Affairs (MHA) on Monday decided to create five new districts in the Union Territory of Ladakh.The new districts are Zanskar, Drass, Sham, Nubra and Changthang. Union Home Minister Amit Shah, on X platform, said, "In pursuit of PM Shri @narendramodi Ji's vision to build a developed and prosperous Ladakh, the MHA has decided to create five new districts in the union territory. The new districts, namely Zanskar, Drass, Sham, Nubra and Changthang, will take the benefits meant for the people to their doorsteps by bolstering governance in every nook and cranny." "The Modi government is committed to creating abundant opportunities for the people of Ladakh," Shah said.

बॉस हो तो चौधरी साब जैसा

70 कर्मचारियों को बना दिया करोड़पति, कैसे हुआ ये चमात्कार?

आमतौर पर कई कंपनियों के कर्मचारी अपने बॉस को कोसते रहते हैं। इसके पीछे वजह भी है क्योंकि कुछ बॉस अपने कर्मचारियों को बेवजह का तनाव देते हैं। लेकिन एक बॉस ऐसा भी है, जिसने अपने कर्मचारियों को रातोंरात करोड़पति बना डाला। बॉस के इस फैसले से कर्मचारी इतने खुश और उत्साहित हैं कि कह रहे हैं कि बॉस हो तो चौधरी साब जैसा...

दरअसल, भारतीय-अमेरिकी अरबपति जय चौधरी अपना पहला स्टार्टअप बेचने जा रहे थे। जब यह खबर लगी तो कर्मचारियों में मायूसी छा गई। भला कौन चाहेगा कि उनकी वो कंपनी बिक जाए और सारे कर्मचारी सडक पर आ जाए। लेकिन कर्मचारियों को इस बात का अहसास ही नहीं था कि उनके बॉस जय चौधरी उनकी 7 पुश्तों के लिए इंतजाम करने जा रहे हैं। क्लाउड-सिक्योरिटी कंपनी जी स्केलर के सीईओ जय चौधरी ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने जब अपना स्टार्टअप बेचा तो अपने 70 कर्मचारियों को करोड़पति बना दिया।

☞ **क्या है कर्मचारियों के करोड़पति बनने की कहानी** :- 90 के दशक में 65 साल के जय चौधरी ने अपनी पत्नी ज्योति के साथ मिलकर Secure IT नाम की कंपनी शुरू की थी। अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी इसी में खपा दी थी। जय चौधरी ने CNBC को बताया कि कंपनी के निवेशकों ने उन्हें अपनी कंपनी के भीतर कर्मचारियों को इक्विटी (शेयर) देने की परमिशन दी थी। इसी के चलते उन्होंने अपने बहुत से कर्मचारियों को इक्विटी दी हुई थी।

☞ **ऐसे मिला भयंकर फायदा** :- 1998 में जब उन्होंने अपनी कंपनी Verisign को बेची तो जय चौधरी ही नहीं, बल्कि उनके कर्मचारियों को भी तगड़ा वित्तीय लाभ मिला। उसके बाद आने वाले वर्षों में वेरिसाइन के स्टॉक की कीमतों में उछाल आया, जिससे उनके 80 में से 70 से अधिक कर्मचारी करोड़पति बन गए, कम से कम कागज पर तो यही दिख रहा था। कुल मिलाकर, 87.5 प्रतिशत कर्मचारी करोड़पति हो गए. जय चौधरी ने CNBC को बताया कि इक्विटी दिया जाना अच्छा होता है, क्योंकि वही कर्मचारी कंपनी को ऊपर लेकर जाते हैं, वही दिन-रात काम करते हैं।

☞ **क्या बोले करोड़पति कर्चमारी** :- जय चौधरी के मुताबिक CNBC को बताया कि कंपनी में लोग बहुत उत्साहित थे, क्योंकि उन्होंने कभी इतनी बड़ी रकम के बारे में नहीं सोचा था। कई कर्मचारी नए घर और गाड़ियां खरीद रहे थे या कुछ समय के लिए काम से छुट्टी ले रहे थे। वे जो करना चाहते थे, कर सकते थे।

☞ **कौन हैं जय चौधरी** :- जय चौधरी का जन्म 1959 में हिमाचल प्रदेश में ऊना के पनोह गांव में हुआ था। उनके पिता किसान थे, नाम था भगत सिंह चौधरी। जय चौधरी का पूरा नाम जगतार सिंह चौधरी है। जगतार स्कूल आने-जाने के लिए रोज 8 किलोमीटर पैदल चला करते थे। उन्होंने बीएचयू से अपनी ग्रेजुएशन की और उसके बाद 1982 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी से एमबीए की डिग्री हासिल की। सिनसिनाटी में पढ़ाई करने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी, जिसकी बाबत वे विदेश जाकर पढ़ पाए। जय चौधरी ने अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आईबीएम और यूनिसिस में काम किया। 2008 में उन्होंने जी स्केलर बनाई। ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी मुहैया करवाती है। दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां उनकी क्लाइंट हैं। 2018 में जी स्केलर का प्प्ब आया और ये एक छेंकुं लिस्टेड कंपनी बन गई थी।

☞ **कितनी है जय चौधरी की नेटवर्थ** :- forbes.com के मुताबिक 27 अगस्त 2024 तक जय चौधरी की नेट वर्थ 11.3 बिलियन डॉलर (करीब-करीब 10 हजार करोड़ रुपए) है। वह और उनके परिवार के पास Zscaler में 40 फीसदी की हिस्सेदारी है। Zscaler बनाने से पहले जय चौधरी ने चार कंपनियां बनाई थीं, जिनमें सिक्योर आईटी, कोरहार्बर, साइफरट्रस्ट और एयरडिफेंस शामिल थीं। इन चारों कंपनियों को ही बाद में अलग-अलग कंपनियों ने अधिग्रहित कर लिया था।

Why is India's PM Modi visiting Ukraine after Russia?

Kyiv is due to welcome Indian Prime Minister Narendra Modi on August 23, on the eve of Ukrainian Independence Day, and just over a month after Modi visited Moscow. His visit is sure to envoke mixed feelings among his Ukrainian hosts. India has persevered in maintaining close ties to Russia despite the full-scale invasion of Ukraine in February 2022, at the cost of significant irritation to Kyiv and its allies. While Modi has called for peace, he has also refused to directly hold the Kremlin responsible for the war. This was also illustrated during Modi's trip to Russia in July and his meeting with President Vladimir Putin, which coincided with Moscow's deadly attack on a Ukrainian children's hospital. The Indian prime minister responded with a carefully worded comment. "When innocent children are killed, the heart bleeds and that pain is very terrifying," Modi said at the time.

First visit of Indian leader to Ukraine in decades

In turn, Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy described Modi's visit to Russia as a "disappointment." "It is a huge disappointment and a devastating blow to peace efforts to see the leader of the world's largest democracy hug the world's most bloody criminal in Moscow on such a day," Zelenskyy wrote online.

Now, Modi is set to make his first visit to Ukraine since the war began in February 2022, and the first visit by an Indian leader to Ukraine for about 30 years. "India has substantive and indepen-

former Indian ambassador, and a distinguished fellow at the Gateway House think tank, told DW. "India wants to expand, consolidate and maintain its ties with Russia," he said, adding that New Delhi was not concerned that the Kyiv visit could jeopardize India's relations with Moscow.

Tiptoeing between US, Russia, China

Military, trade and diplomatic ties between Russia and India already run deep. India purchases over 40% of its oil and 60% of its armaments from Russia, and also imports significant amounts of coal, fertilizer, vegetable

dent ties with both Russia and Ukraine and these partnerships stand on their own," Tanmaya Lal, Secretary (West) at the Indian Ministry of External Affairs (MEA) told reporters during a media briefing on Monday.

India wants peace talks

Experts say that this visit is a balancing act for India, which also gives New Delhi a chance to urge peace negotiations. But Indian diplomacy has to maintain a difficult balance. "Russia is a long-term traditional ally and Ukraine also has had very friendly relations with India. It is a difficult task to manage this, especially because Ukraine has received strong support from the West, with which India also has good relations," Rajiv Bhatia,

oil and precious metals. The fact that Russia is being shunned by the West over the Ukraine invasion is working in India's favor, as it motivates Moscow to pursue even closer ties. Also, New Delhi is wary that alienating Moscow could push Russia closer to China, which is India's major rival in Asia. Complicating the geopolitical calculation even further, the US and other Western countries are irritated by Modi's Russia-friendly stance and by his meeting with Putin. However, the West also doesn't want India to lose this influence in Moscow, as India could serve as a counterbalance to China when trying to sway the Kremlin.

What will Modi do in Kyiv?

"India will try to project itself as a peacemaker and engage in humanitarian assistance," Amit Julka, an assistant professor of International Relations at Ashoka University, told DW. "Despite India's closeness to the US, there are undercurrents of suspicion. The Ukraine visit will also serve as damage control in terms of the optics. While it enjoys close ties with Russia, India does not want to alienate the West," Julka said. India's Foreign Ministry said that New Delhi would not unveil a peace plan in Kyiv, but India was ready to support the negotiation of a peace settlement.

What else is on the agenda?

Apart from Russia's war on Ukraine, there are several other items on that Modi will likely discuss with Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy. "Defense and economic cooperation, and the role of India in the eventual rebuilding of post-war Ukraine will also be discussed," said former ambassador Bhatia. "Modi is also likely to express gratitude towards the Ukrainian government for their help in evacuating Indian students after the war broke out," he added. The Indian Ministry of External Affairs says there are about 21,000 Indian students currently enrolled in Ukrainian universities. With full-scale war breaking out in 2022, India, Ukraine and Poland worked together to evacuate most of them in a push dubbed "Operation Ganga."

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि
(अधिवक्ता)
Ph.- 9308454485
7004408851
E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

★ किसी आपराधिक मामले की सुनवायी के लिए कोई मजिस्ट्रेट के यहां से अगर किसी दूसरे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रावधान है?

किसी आपराधिक मामलों की सुनवाई अगर किसी न्यायिक दंडाधिकारी के यहां चल रहा हो और किसी पक्ष कार को यदि है लगता है कि वह कोर्ट दूसरे पक्ष कार के तरफ से काम कर रहे हैं और प्रथम पक्ष कार की बात को नहीं सुना जा रहा है जिसके वजह से उसे न्याय नहीं मिल पाएगा तो इस संबंध में आप मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां केस्को किसी अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां ट्रांसफर करवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 410 में यह प्रावधान है कि कोई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अपने अधीनस्थ किसी न्यायिक दंडाधिकारी से किसी मामले को वापस ले सकता है या किसी मामले को जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया है वापस मंगा सकता है और मामले की जांच या विचारण स्वयं कर सकता है या उसे जांच या विचारण के लिए किसी अन्य ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है जो उसकी जांच या विचारण करने के लिए सक्षम हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 410(2) मैं यह प्रावधान किया गया है कि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी मामले को जो उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 192 की उप धारा 2 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले किया है वापस मंगा सकता है और ऐसे मामले को जांच या विचारण स्वयं कर सकता है।

★ आपराधिक पुनरीक्षण अर्थात क्रिमिनल रिवीजन क्या होता है?

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 399 के अंतर्गत कोई सेशन न्यायाधीश व्यापक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 401 के अंतर्गत प्रयोग कर सकता है। निम्न आपराधिक न्यायालय से अभिलेख की मांग करने की शक्ति उच्च न्यायालय के साथ-साथ सेशन न्यायालय को भी प्रदत्त की गई है। पुनरीक्षण का आधार तब उत्पन्न होता है जब न्यायालय के किसी कार्यवाही में आदेश का उद्देश्य अनुचित अनियमित और अवैध रहा है। दंड आदेश के किसी भी त्रुटि को केवल उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण की शक्ति के प्रयोग से ही दूर किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 398 के अधीन उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय उनमोचन के सभी मामलों में वह सीआरपीसी की धारा 249 के अंतर्गत या सीआरपीसी की धारा 245 के अंतर्गत अतिरिक्त जांच का आदेश दे सकते हैं। उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय सक्षम है उन मोचन के आदेश को खारिज करने के लिए और तथ्यों की अतिरिक्त अन्वेषण करने या साक्ष्य पर पुन: विचार हेतु निर्देश देने के लिए और इस प्रकार अतिरिक्त जांच के लिए निर्देश दे सकते हैं। लॉ कमीशन ने न्यायालय की पुनरीक्षण करने की शक्तियों में बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया है परिणाम स्वरूप दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए गए हैं। उदाहरण स्वरुप 1973 के पूर्व उच्च न्यायालय इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर अर्थात अंतर्वेती आदेश के संबंध में पुनरीक्षण में हस्तक्षेप कर सकता था परंतु इस प्रावधान का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने लगा इसलिए सीआरपीसी की धारा 397 के स्पष्टीकरण (2) मैं इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर को पुनरीक्षण से बाहर रखा गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 एक नवीन धारा है जिसमें उन आधारों का वर्णन है जिस पर न्यायालय पुनरीक्षण की अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है। कोई पुनरीक्षण वाद व्यथित पक्षकार के आवेदन पर ग्रहण किया जा सकता है और न्यायालय स्वविवेक पर पुनरीक्षण हेतु कार्यवाही कर सकता है। कोई दूसरा पुनरीक्षण संपोषणीय नहीं है सभी मजिस्ट्रेटों कार्यपालक या न्यायिक के लिए उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय पुनरीक्षण न्यायालय माना जाता है। कोई पक्षकार किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन दाखिल कर सकता है परंतु कोई पक्षकार दोनों न्यायालयों में नहीं जा सकता है जब उसने एक न्यायालय का चुनाव कर लिया है।

★ क्या किसी व्यक्ति से उसको उत्प्रेरित करके या धमकी या किसी प्रकार का वचन देकर किसी अपराध की संस्वीकृति (कन्फेशन) कराई जा सकती है?

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति से उतप्रेरणा ,धमकी या वचन द्वारा किसी अपराध की संस्कृति करवाई गई है तो वह सुसंगत नहीं होगी अर्थात मान्य नहीं होगी। अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्कृति दांडीक कार्यवाही में विसंगत होती है यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को यह लगता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में कन्फेशन वह ऐसी उत्प्रेरण धमकी या वचन द्वारा कराई गई है जो किसी सक्षम व्यक्ति की ओर से कराया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त होगी वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे उचित प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाही के बारे में ऐहिक रूप का कोई फायदा उठाएगा या ऐहिक रुप के किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा।

★ क्या किसी अपराधी द्वारा अगर पुलिस के सामने अपना दोष स्वीकार किया गया हो तो इस आधार पर उसको सजा हो सकती है?

अगर किसी अपराधी द्वारा पुलिस अफसर के सामने अपना दोष स्वीकार किया जाता है तो केवल इस आधार पर उसके कन्फेशन को साबित नहीं किया जा सकता है कि उसने अपना दोष स्वीकार कर लिया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अनुसार पुलिस के सामने कन्फेशन को साबित नहीं किया जा सकता है साथ ही अगर किसी व्यक्ति ने पुलिस कस्टडी में रहते हुए कोई कन्फेशन किया हो तो इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 में प्रावधान है कि कोई भी कन्फेशन जो किसी व्यक्ति ने उस समय की है जब वह पुलिस अफसर की कस्टडी में है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उसका कन्फेशन उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी जब तक की उसका कन्फेशन मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ना की गई हो परंतु अगर किसी अपराध के बारे में अभियुक्त ने कन्फेशन किया हो और उसके कन्फेशन के आधार पर अपराध में इस्तेमाल किए गए कोई वस्तु कोई हथियार या कोई और जानकारी उसके द्वारा बताए गए स्थानों से प्राप्त होती है तो वह प्राप्त जानकारी या वस्तु या हथियार को न्यायालय में साबित किया जा सकता है इस बात की व्यवस्था भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में किया गया है।

शुद्ध चावल एवं मक्के के आटे से निर्मित नमकीन

Dhunky
NAMKEEN

Shree Shyamji Udyog

गजब स्वाद की ! गजब कहानी !

fssai

Lic No. 10042411000004

Veg Biryani
masala pola
katori chaat
rings
snacks

Expanding our Namkeen family!
Dealers inquiries welcome, contact us today!

NEAR JAI PRAKASH EVENING INTER COLLEGE
JANDAHA ROAD HAJIPUR (VAISHALI)
MOB: 7782053204

MADE IN INDIA

PURE

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
(Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC

AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D

SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
Industrial area, Fatuha-803201
E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.:0162-3500233/2950008

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
Dispersing Happiness